रजिस्ट्री सं० डी(डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1976/अग्रहायण 27, 1898

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1976/AGRAHAYANA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1976

का० आ० 4705—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सिंडीकेट बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम प्रथमा बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से प्रथमा बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं।

3 बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) :— बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न को) निर्विष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशकों को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशनों के ये कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जायेंगे उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए०सी० (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Banking)

(Banking Wing)

New Delhi, the 25th November, 1976

S.O. 4705.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Syndicate Bank, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Prathama Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Prathama Bank ;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified areas as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation signed by the last signatory to the business.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1)(a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulated of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(1)]

का०आ० 4706.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :— बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इकतीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) :—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए०सी० (2)]

S.O. 4706.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and the State Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1)(a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulated of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(2)]

का० आ० 4707.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम हरयाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से हरयाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिनियत क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) :—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो तो, उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन को कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशकों को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (3)]

S.O. 4707.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank, makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Haryana Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Haryana Kshetriya Gramin Bank ;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1)(a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initiated or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(3)]

का०आ० 4708.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन—अधिवेशन का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन—(1) अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन:—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्विष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं० एफ० 4-33/76-ए०सी०(4)]

S.O. 4708.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and United Commercial Bank, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified areas as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that

purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be there.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1)(a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(4)]

का०आ० 4709.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम गौड़ ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से गौड़ ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उसके अधिनियम में है ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या:—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान:—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) :—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए

अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख:—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अंतिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए०सी० (5)]

S.O. 4709.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and United Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Gaur Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Gaur Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting : A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to make part in the discussion of, or vote at a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum :—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (herelnafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may

be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(5)]

का० आ० 4710.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या:—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन:—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान:—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची:—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन:—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन:—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालन किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

11. कारबार के अभिलेख:—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अंतिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं० एफ० 4-33/76-ए०सी० (6)]

S.O. 4710.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bhojpur Rohtas Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Bhojpur Rohtas Gramin Bank ;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meeings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day, is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a). The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(6)]

का० आ० 4711.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय, रिजर्व बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या:—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन:—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान:—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची:—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन:—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलाएगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन:—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इससे इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएगें ।

(5) अधिवेशनों के ये कार्यवृत्त, जो इन नियमों के अपबन्धों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (7)]

S.O. 4711.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Union Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Samyut Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Samyut Kshetriya Gramin Bank ;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

2. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(7)]

का० आ० 4712.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ है जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या:—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन:—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान:—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची:—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन:—(1) अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने अथवा मत देने में असमर्थ हो वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन:—यदि बोर्ड का अधिवेशन गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन सप्ताह में उसी दिन उसी स्थान एवं समय के लिए अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो तो उससे अगले दिन जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख:—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ यथास्थिति अध्यक्ष अथवा निदेशक जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशकों को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएगें।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएगे उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों के साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (8)]

S.O. 4712.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four:

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any busines circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(8)]

का० आ० 4713.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और केनरा बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या:—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन:—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान:—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची:—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड आपात का अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन:—(1) अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी:

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन:—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा:

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख:—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (9)]

S.O. 4713.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Canara Bank, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Tungabhadra Gramin Bank, (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Tungabhadra Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1)(a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business or circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four:

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place:

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(9)]

का० आ० 4714.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का नाम पुरी ग्राम्य बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से पुरी ग्राम्य बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान:—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्विष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा। मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा अद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जाएगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए०सी० (10)]

S.O. 4714.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Indian Overseas Bank, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Puri Gramya Bank, (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Puri Gramya Bank ;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1)(a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four:

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place:

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a). The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F.-33/76-AC(10)]

का० आ० 4715.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और दी जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि० के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम जम्मू रूरल बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से जम्मू रूरल बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या:—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन:—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान:—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची:—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन:—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी:

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन:—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निविष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख:—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्य वृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जाएगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएगें।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (II)]

S.O. 4715.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and the Jammu & Kashmir Bank Limited, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jammu Rural Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Jammu Rural Bank;

(c) words and expressions used here in and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—The meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next suceeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(11)]

का०आ० 4716.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

(8) अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) :—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशकों को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (12)]

S.O. 4716.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank

of India and Central Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Champaran Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976 .

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Champaran Kshetriya Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarly be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC (12)]

का०आ० 4717.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम बाराबंकी ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से बाराबंकी ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या:—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन:—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची:—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन:—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी:

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन:—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा:

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निविष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख:—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इससे इसमें पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (13)]

S.O. 4717.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Barabanki Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Barabanki Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarly be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjouurned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holliday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1)(a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(13)]

का० आ० 4718.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सिंडिकेट बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम रायलासीमा गुडगांव ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से गुडगांव ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या:—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन:—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची:—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन:—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इकतीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन:—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए

अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख:—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात्, यथासीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशनों के ये कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (14)]

S.O. 4718.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Syndicate Bank, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Gurgaon Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requiries,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Gurgaon Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarters.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1)(a) The Chairman shall decide the time and place of every meetings of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Boad, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than director who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1)(a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(14)]

का० आ० 4719.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक आफ बड़ौदा के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या:—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन:—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान:—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची:—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन:—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी:

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा(4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थान:—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख:—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (15)]

S.O. 4719.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of Baroda, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Rae Bareli Kshetriay Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1)(a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reasons of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, as the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than director who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1)(a). The minutes of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(15)]

का०आ० 4720.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम)—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और भावी कर होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

11. कारबार के अभिलेख—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं० एफ० 4-33/76-ए०सी०(16)]

S.O. 4720.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Farrukhabad Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Farrukhabad Gramin Bank ;

(c) words and expressions used herein and not defined but definied in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjouruned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a). The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC (16)]

का० आ० 4721.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम मल्लभूम ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से मल्लभूम ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या.—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन.—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान.—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची.—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन.—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम).—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

11. कारबार के अभिलेख—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (17)]

S.O. 4721.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and United Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Mallabhum Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Mallabhum Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1)(a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC (17)]

का० आ० 4722.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम बोलंगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम)—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निविष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

11. कारबार के अभिलेख—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं० एफ 4-33/76-ए० सी० (18)]

S.O. 4722.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and the State Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bolangir Anchalik Gramya Bank (Meetings of Board) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Bolangir Anchalik Gramya Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1)(a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F-4-33/76-AC (18)]

का० आ० 4723.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम नागार्जुन ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से नागार्जुन ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करें ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम)—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन:—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

11. कारबार के अभिलेख—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों के साक्ष्य होंगे ।

[सं० एफ० 4-33/76-ए०सी० (19)]

हृषीकेश गुहा, अवर सचिव

S.O. 4723.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India and the State Bank of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Nagarjuna Grameena Bank (Meeting of Board) Rules, 1976

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Nagarjuna Grameena Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the chairman.

5. Venue of the meetings.—The meeting of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four:

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1)(a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(19)]

H. K. GUHA, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1976

(आय-कर)

का० आ० 4724.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी अधिसूचना सं० 1448 [फा० सं० 191/30/76 आई० टी० (ए० 1)] तारीख 20-8-76 में निम्नलिखित परिवर्धन करता है :—

स्तम्भ 3 के अधीन क्रम संख्या 19क के सामने मद सं० 1 में निम्नलिखित जोड़े जाएंगे :—

वेतन और प्रतिदाय सर्किल-1, पुणे ।

वेतन और प्रतिदाय सर्किल-2, पुणे ।

वेतन और प्रतिदाय सर्किल-3, पुणे ।

[सं० 1487/फा० सं० 191/30/76-आ०टी० (ए० I)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 16th September, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 4724.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following additions to its Notification No. 1445 (F. No. 191/130/76-IT(A1) dated 20-8-76.

Against Sl. No. 19A under column 3, the following shall be added to item No. 1:—

Salaries and Refunds Circle-I, Poona.
Salaries and Refunds Circle-II, Poona.
Salaries and Refunds Circle-III, Poona.

[No. 1487/F. No. 191/30/76-IT(A1)]
M. SHASTRI, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1976

का० आ० 4725.—आय कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 एफ की उप-धारा (6) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 22 जुलाई 1974 के आदेश सं० 60-फा० सं० 328/137/74-धन कर के आंशिक संशोधन में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा, विशेष रूप से उल्लेख करता है कि इस आदेश में संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आय कर आयुक्त, उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में लिखित तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारियों के संबंध में आयुक्त होगा।

यह आदेश 4-10-1976 को लागू होगा।

सारणी

1	2	3
1.	आय-कर आयुक्त, आंध्र प्रदेश-II, [हैदराबाद	निरीक्षी सहायक आय कर आयुक्त, अभिग्रहण रेंज, हैदराबाद तथा काकीनाड़ा।

[सं० 101/76/फा०सं० 316/185-76 धन कर]

एच० एन० मंडल, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th September, 1976.

S.O. 4725—In exercise of the powers conferred by the Explanation to sub-section (6) of section 269F of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of order No. 60-F. No. 328/137/74-WT dated 22nd of July, 1974, the Central Board of Direct Taxes hereby specifies that the Commissioner of Income Tax specified in column (2) of the Table appended to this order shall be the Commissioner in relation to the Competent Authority or Competent Authorities specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

This order shall come into force on 4-10-1976.

TABLE

(1)	(2)	(3)
1.	Commissioner of Income-tax, Andhra Pradesh-II, Hyderabad.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Ranges Hyderabad and Kakinada.

[No. 101/76/F. No. 316/185/76-WT]
H. N. MANDAL, Under Secy

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय गुन्टुर-4 (आ० प्र०)

(केन्द्रीय उत्पादन शुल्क)

गुंटुर, 25 सितम्बर, 1976

का० आ० 4726.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित श्रेणी के सभी अधिकारियों को उनके अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामने बताए गये नियमों के अन्तर्गत उसी सारणी के स्तम्भ 4 में बतायी गयी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्रदान करता हूं।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पद-नाम	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम संख्या	शर्तें और सीमायें
1	2	3	4
1	सहायक समाहर्ता	192बी व्याख्या	शुल्क दायित्व निश्चित करने के प्रयोजनार्थ यूनिट के बन्द होने की अवधि वर्जित करना।

[अधिसूचना सं० 3/76/सी० सं० 4/8/1/76एम०पी० 2]

सी० भुजंगस्वामी, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE : GUNTUR-4 (A.P.)

(CENTRAL EXCISE)

Guntur, the 25th September, 1976

S.O. 4726—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I empower all the officers of the rank mentioned in Column 2 of the table appended below to exercise within their jurisdictions the powers of the Collector under rules mentioned against each in column 3 of the said Table subject to conditions, if any, indicated in column 4 thereof :—

TABLE

Sl. No.	Designation of the Officer	Central Excise Rule No.	Conditions and limitations
1	2	3	4
1.	Assistant Collector	92B Explanation (c)	To exclude the period of closure of unit for purposes of computing the duty liability.

[Notification No. 3/76/C. No. IV/8/1/76 MP2.]

C. BHUJANGASWAMY, Collector

आयकर आयुक्त कार्यालय विदर्भ एवम् मराठवाड़ा, नागपुर

नागपुर, 13 अक्तूबर, 1976

(आय-कर)

का० आ० 4727.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 124 की उपधारा 2 के अन्तर्गत 16 अगस्त 1974 को जारी की गई इस कार्यालय की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में आयकर आयुक्त विदर्भ और मराठवाड़ा, नागपुर एतद्द्वारा आयकर अधिकारी, सर्वेक्षण सर्किल नागपुर के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अनुसूची में संशोधन करने का निर्देश देते हैं। संशोधन नीचे दिए अनुसार है।

अनुसूची

क्रम संख्या/आयकर अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1. आयकर अधिकारी सर्वेक्षण सर्किल, नागपुर	नीचे दिए गए जिलों से संबंधित सर्वेक्षण कार्यों के परिणामस्वरूप सामान्य सूची रजिस्टर (जी० आई० आर०) में लिए गए मामले । 1. नागपुर 2. भंडारा निम्नलिखित जिलों के मामलों को छोड़कर 1. वर्धा 2. चन्द्रपुर 3. यवतमाल

2. आयकर आयुक्त विदर्भ एवम् मराठवाडा, नागपुर इसके आगे यह निर्देश देते हैं कि आयकर अधिकारी, सर्वेक्षण सर्किल द्वारा अब तक सम्पन्न किए जाने वाले वर्धा, चन्द्रपुर और यवतमाल जिलों के क्षेत्रों से व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों, या मामलों या मामलों की श्रेणियों या आय या आय की श्रेणियों से संबंधित कार्य उस प्रभारी आयकर अधिकारी द्वारा संपन्न किए जायेंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र आता हो जिसमें करदाता रहता है या व्यवसाय धंधा या व्यापार करता है ।

यह अधिसूचना 1-11-76 से प्रभावी होगी ।

[सं० एस आई बी/पी आर/सर्वे सर्किल/6/74-75]

के० एन० अनन्तराम अय्यर, आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, VIDARBHA AND MARATHWADA, NAGPUR

Nagpur, the 13th October, 1976

(INCOME-TAX)

S.O.4727—In partial modification of this office Notification dated 16-8-1974 issued under Sub-Section (2) of Section (124) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Commissioner of Income-tax, Vidarbha and Marathwada, Nagpur hereby directs to modify the Schedule in respect of the jurisdiction of Income-tax Officer, Survey Circle, Nagpur is as under :—

SCHEDULE

S. No.	Designation of the I.T.O.	Jurisdiction.
1.	Income-tax Officer, Survey Circle, Nagpur.	Cases which will be taken on GIR as a result of Survey operations pertaining to the following districts. 1. Nagpur. 2. Bhandara. Except the cases of following districts. 1. Wardha 2. Chandrapur. 3. Yavatmal.

2. The Commissioner of Income-tax, Vidarbha and Maraee-wada, Nagpur further directs that the functions which wle, hitherto performed by the Income-tax Officer, Survey Circor Nagpur in respect of areas, persons or classes of persons all cases or classes of cases or incomes or classes of incomes shr's henceforth be performed by the charge Income-tax Officees having jurisdiction over the areas in which the assessee resids or carries on business, profession or vocation of Wardha, Chandrapur and Yavatmal districts respectively.

This Notification shall take effect from 1-11-1976.

[No. SIB/PR/Survey Circle/6/74-75]

K. N. ANANTHARAMA AYYAR, Commissioner

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय, (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

का० आ० 4728.—सर्वश्री रौनक इन्टरनेशनल (प्रा०) लि०, 17-पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली जो एक पात्र निर्यात सदन है ने अप्रैल/मार्च 1975 अवधि के दौरान लाइसेंस के लिए संलग्न सूची के अनुसार प्रशीतकार और अन्य मदों का आयात करने के लिए 1,49,920/- रुपए के लिए हस्तांतरण द्वारा लाइसेंस संख्या पी/एल/2728797, दिनांक 2-8-74 प्राप्त किया था । उन्होंने लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति 85,398/- रु० तक उपयोग में लाने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और शेष 64,522/- रुपए है जिनका उपयोग नही किया गया है ।

अपने तर्क के समर्थन में कथित निर्यात सदन ने आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक नियम तथा क्रियाविधि 1975-76 के पैरा 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई। अस्थानस्थ हो गई है ।

अद्यतन तथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, दिनांक 7-12-55 की धारा 9(सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं लाइसेंस को रद्द करने का आदेश देता हूं ।

कथित निर्यात सदन को लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के मामले पर अब आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक नियम तथा क्रियाविधि 1975-76 के पैरा 320 के अनुसार विचार किया जाएगा ।

[संख्या:—ई० एच/आर-1/ए एम'75/एस सी-6/सीएलए]

बनारसी दास, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports (Central Licensing Area), New Delhi

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 1st April, 1976

S.O. 4728.—M/s. Ranuaq International (P) Ltd., 17 Parliament Street, New Delhi, an eligible Export House, had acquired Licence No. P/L/2728797 dt. 2-8-74 for Rs. 1,49,920/- by transfer during AM' 75 period for the import of Refrigerants and other items as per list attached with the licence. They have applied for issue of Duplicate Customs Copy of the licence on the ground that the original Customs Copy of the licence has been lost/misplaced having been utilised for Rs. 85,398/- and the balance of Rs. 64,522/- remains un-utilised.

The captioned Export House has filed an affidavit on stamped paper in support of their contention as required under para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1975-76. I am satisfied that the original Customs Copy of the Licence has been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under Clause 9 (cc) Import (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended upto date, I order the cancellation of the licence.

The captioned Export House case will now be considered for the issue of duplicate Customs Copy of the licence in accordance with para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1975-76.

[No. EH/R-1/AM'75/SC-VI/CLA]

BANARSI DASS, Dy. Chief Controller

मुख्य-नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1976

का० आ० 4729.—सामाजिक कार्य के लिए क्रिश्चियन एजेन्सी, राहत एवं विकास "कासा" मासे हाल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली को प० जर्मनी से 18 कोसिस 3400 किलो ग्राम अन्धों के लिखने का कागज आयात करने के लिए 23,847/- रुपए (तेइस हजार आठ सौ सैंतालीस रुपए मात्र) मूल्य का सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी०/जे/3043763/एन/एमसी/47/एच/35-36/आइएल एस, दिनांक 4-5-73 प्रदान किया गया था । पार्टी ने अब सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गई है । लाइसेंस धारी ने आगे यह भी बताया है कि वह विषयाधीन माल जिसके लिए यह लाइसेंस जारी किया गया था, एक बौंड के अधीन रिहा कर दिया गया था और सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक अनुलिपि प्रति की मांग की है ।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे०/3043763/एन/एमसी/47/एच/35-36/आईएलएस, दिनांक 4-5-73 खो गया है तथा निदेश देता है कि उनको एक सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए । मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[संख्या 55/सोसायटी/एएम-73/आईएलएस]

Office of the Chief Controller of Imports and Exports
New Delhi

ORDER

New Delhi, the 24th November, 1976

S.O. 4729.—Christian Agency for Social Action, Relief and Development 'CASA', Massay Hall, Jaisingh Road, New Delhi was granted a customs clearance permit No. P/J/3043763/N/MC/47/H/35-36/ILS dated 4-5-73 for the import of 18 cases 3400 kgs of Blind writing paper from West Germany, valued Rs. 23847/-. (Rupees Twenty three thousand eight hundred and forty seven only). The party have now applied for the issue of a duplicate customs clearance permit on the ground that the original customs clearance permit has been lost. It has been further reported by the licensee that the goods in question for which this licence was issued were cleared under a bond and the customs have asked for a duplicate.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit. The under signed is satisfied that the original customs clearance permit No. P/J/3043763/N/MC/47/H/35-36/ILS dt. 4-5-73 has been lost and directs that a duplicate customs clearance permit be issued to them. The original is hereby cancelled.

[File No. 55/Society/AM-73/ILS]

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1976

का० आ 4730.—अधीक्षक अभियन्ता (हिदल) यमुना स्टेज 1 और 2 सर्किल, उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत बोर्ड, देहरादून को 220 के वी छिबरो खेदरी के फालतू पुर्जों के लिए लाइसेंस सं० जी/ए/1067840, दिनांक 8-1-76 प्रदान किया गया था । अधीक्षक अभियन्ता ने सूचित किया है कि लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है और उन्होंने उस की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए निवेदन किया है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए ।

3. लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द कर दी गई समझी जाए । उसकी एक अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या 3/एसजी/218/75-76/पीएलएस/बी/1238]

एल प्रसाद, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते मुख्य-नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 1st December, 1976

S.O. 4730.—The Superintending Engineer (Hydel) Yamuna Stage I & II Circle, U.P. State Electricity Board, Dehradun was granted licence No. G/A/1067840 dt. 8-1-76 for spares for 220 KV Chibro-Khodri. The Superintending Engineer has reported that the Exchange Copy of the licence has been misplaced and he has requested to issue duplicate copy of the same.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the Exchange copy of the licence has been lost and directs that the duplicate copy of the said exchange purpose copy of the licence be issued.

The Original Exchange purpose copy of the licence has been treated as cancelled. A duplicate copy of the same is being issued separately.

[File No. 3/SG/218/75-76/PLS/B/1238]

L. PRASAD, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1976

का० आ० 4731.—श्री डी० कुमार, 28-तुगलक क्रीसेंट, नई दिल्ली को इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान एवम् साहित्य की पुस्तकों के आयात के लिए 5,000 रुपए (पांच हजार रुपए मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस, सं० पी/ए०/1397003/सी/एक्स एक्स/51/एच/39-40, दिनांक 23-5-1974 प्रदान किया गया था । उन्होंने अब लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पंजीकृत कराने के पश्चात् और आंशिक रूप से उपयोग में लाने के बाद अस्थानस्थ हो गई है । पूर्ण धनराशि जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया था, 5,000 रुपए है और अब शेष धनराशि 3,8644.10 के लिए अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है । इस तर्क के समर्थन में उन्होंने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है ।

मैं सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1397003, दिनांक 23-5-74 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ/खो गई है तथा निदेश देता हूं कि आवेदक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति का अनुलिपि जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

[सं० 169-170-4/4/एएम-75/एएलएस/772]

एस० के० बट्टा, उप-मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 30th November, 1976

ORDER

S.O. 4731.—Smt. D. Kumar, 28, Tughlak Crescecent, New Delhi was granted an import licence No. P/A/1397003/C/XX/51/H/39-40 dated 23-5-1974 for Rs. 5,000/- (Rs. Five thousand only) for the import of Books on History, Economics, Politics, Sociology, other Social Sciences and Literature. She has now applied for a duplicate Exchange Control Copy of the licence on the grounds that the original Exchange Control Copy of the licence has been misplaced after having been registered and utilised partly. The total amount for which the licence was issued is Rs. 5,000/- and the duplicate is now required to cover he balance of Rs. 3,844.10. In support of this contention, she has filed an Affidavit. I am satisfied that the original Exchange Control Copy of the licence No. P/A/1397003 dated 23-5-74 has been misplaced/lost and direct that a duplicate Exchange Control Copy of the licence should be issued to the applicant. The original Exchange Copy of the licence is cancelled.

[F. No. 169-170-IV/4/AM-75/ALS/772]

S. K. BATTA, Dy. Chief Controller

नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1976

का० आ० 4732.—भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 के उपखण्ड (ii) दिनांक 1976-09-25 में एस ओ संख्या 3435 दिनांक 1976-09-07 के अधीन प्रकाशित जिस तत्कालीन उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना में IS: 771-1963 कांचाभ मिट्टी के सेनीटरी साधनों की विशिष्टि (पुनरीक्षित) के निरस्त होने की सूचना छपी थी, वह अधिसूचना अब वापस ले ली गई है।

[सं० सीएमडी/13:7]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 25th November, 1976

S.O. 4732.—In the then Ministry of Industry & Civil Supplies (Department of Industrial Development) (Indian Standards Institution) Notification Published under No. S.O. 3435 dated 1976-09-07 in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1976-09-25 notifying the cancellation of IS: 771-1963 Specification for glazed earthenware sanitary appliances (revised), may be treated as withdrawn.

[No. CMD/13 : 7]

का० आ० 4733.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिन्ह निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन शाब्दिक विवरण और भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त ये मानक चिन्ह उनके आगे दी गई तिथियों से लागू होंगे।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पद-संख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS:1711 ISI	स्वतः बंद होने वाली टोंटियां	IS : 1711–1970 स्वतः बंद होने वाली टोंटियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-10-01
2.	IS:1784 ISI	ड्रमों के पेंचदार ढक्कन	IS : 1784–1961 ड्रमों के पेंचदार ढक्कनों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1976-09-16
3.	IS:2389 ISI	परिशुद्धता वाले छहकोणी काबले (व्यास 1.6 से 5 मिमी तक)	IS : 2389–1968 परिशुद्धता वाले छहकोणी काबलों, पेंचों, ढिबरियों और लॉकनट की विशिष्टि व्यास 1.6 से 5 मिमी तक) (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1974-10-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	IS:3461	फर्श के पीवीसी (विनाइल) ऐस्बेस्टास टाइल	IS : 3461-1966 फर्श के पीवीसी (विनाइल) ऐस्बेस्टास टाइलों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1976-04-16
5.	IS:4588 GRADE B IS:4588 GRADE C	कच्ची प्राकृतिक रबड़	IS : 4588-1974 कच्ची प्राकृतिक रबड़ की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या और मोनोग्राम के नीचे की ओर ग्रेड पदनाम अर्थात् 'ग्रेड बी' और 'ग्रेड सी' दिए गए हैं।	1976-10-01
6.	IS:4654 TYPE 3	पैराफीन मोम	IS : 4654-1974 पैराफीन मोम की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या और मोनोग्राम के नीचे की ओर टाइप पदनाम अर्थात् 'टाइप 3' अंकित किया गया है।	1976-09-16
7.	IS:7680	अमोनिया (अजल) गैस के लिए वेल्डकृत अल्प कार्बन इस्पात के गैस सिलेण्डर	IS : 7680-1975 अमोनिया (अजल) गैस के लिए वेल्डकृत अल्प कार्बन इस्पात के गैस सिलेण्डरों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1976-10-01

[सं० सी०एम०डी०/13 : 9]

S. O. 4733.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark (s), design (s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s)/are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS:1711	Self-closing taps	IS: 1711-1970 Specification for self-closing taps (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-10-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.		Screwed closures for drums	IS: 1784-1961 Specification screwed closures for drums	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1976-09-16
3.		Precision hexagon nuts (diameter range 1.6 to 5 mm)	IS: 2389-1968 Specification for precision hexagon bolts, screws, nuts and lock nuts (dia range 1.6 to 5 mm) (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1974-10-16
4.		PVC(vinyl) asbestos floor tiles.	IS: 3461-1966 Specification for PVC (vinyl) asbestos floor tiles.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1976-04-16
5.		Raw natural rubber	IS: 4588-1975 Specification for raw natural rubber (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consiting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side and the grades designations, namely 'GRADE B' and 'GRADE C' subscribed under the bottom side of the monograms as indicated in the designs.	1976-10-01
6.		Paraffin wax	IS: 4654—1974 Specification for paraffin wax (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side and the type designation, namely 'TYPE 3' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.	1976-09-16
7.		Welded low carbon steel gas cylinder for ammonia (anhydrous) gas.	IS: 7680-1975 Specification for welded low carbon steel gas cylinder for ammonia (anhydrous) gas.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1976-10-01

[No. CMD/13 : 9]

का०आ० 4734.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दिए विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई प्रमाणन चिह्न लगाने की फीसें अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई हैं और ये फीसें उनके आगे दी गई तिथियों से लागू होंगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्वतः बंद होने वाली टोंटिया	IS: 1711—1970 स्वतः बंद होने वाली टोंटियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक टोंटी	5 पैसे	1975-10-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	ड्रमों के पेंचदार ढक्कन	IS : 1784–1961 ड्रमों के पेंचदार ढक्कनों की विशिष्टि	1000 ढक्कन	(1) पहली 100 इकाइयों के लिए 10.00 रुपए प्रति इकाई और (2) 101वीं इकाई और उससे ऊपर की इकाइयों के लिए 5.00 रुपए प्रति इकाई।	1976–09–16
3.	परिशुद्धता वाले छह कोणी काबले (व्यास 1.6 से 5 मिमी तक)	IS : 2389-1967 परिशुद्धता वाले छहकोणी काबलों, पेचों, तिबरियों और लाकनट की विशिष्टि (व्यास 1.6 से 5 मिमी तक (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	25 पैसे	1924–10–16
4.	फर्श के पीवीसी (विनाइल (एस्बेस्टास टाइल	IS 3461-1966 फर्श के पीवीसी (विनाइल) ऐस्बेस्टास टाइलों की विशिष्टि	100 वर्ग मीटर	रु० 2.00	1976–04–16
5.	कच्ची प्राकृतिक रबड़	IS : 4588–1975 कच्ची प्राकृतिक रबड़ की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 10.00	1976–10–01
6.	पराफीन मोम	IS : 4654–1974 पैराफीन मोम की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 5.00	1976–09–16
7	अमोनिया (अजल) गैस के लिए वेल्डकृत अल्प कार्बन इस्पात गैस के सिलेण्डर	IS : 7680–1975 अमोनिया (अजल) गैस के लिए वेल्डकृत अल्प कार्बन इस्पात के गैस सिलेण्डरों की विशिष्टि	एक सिलेण्डर	(1) पहली 5000 इकाइयों के लिए 5.00 रुपए प्रति इकाई और (2) 5001 की इकाई और उससे ऊपर की इकाइयों के लिए 3.00 रुपया प्रति इकाई।	1976–10–01

[सं० सी एम० डी०/13:10]

S.O. 4734.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee (s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed have been determined and the fee (s) shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per unit	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Self-closing taps	IS: 1711-1970 Specification for self-closing taps (first revision)	One Tap	5 Paise	1975-10-01
2.	Screwed closures for drums	IS: 1784-1961 Specification for screwed closures for drums	1000 Pieces	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 100 units and (ii) Rs. 5.00 per unit for the 101st units and above.	1976-09-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Precision hexagon nuts (dia meter range 1.6 to 5 mm)	IS: 2389-1968 Specification for precision hexagon bolts, screws, nuts and lock nuts (dia range 1.6 to 5mm) (first revision)	One Metric Tonne	25 Paise	1974-10-16
4.	PVC (vinyl) asbestos floor tiles.	IS: 3461-1966 Specification for PVC (vinyl) asbestos floor tiles.	100 Square Metres	Rs. 2.00	1976-04-16
5.	Raw natural rubber	IS: 4588-1975 Specification for raw natural rubber (first revision).	One Tonne	Rs. 10.00	1976-10-01
6.	Paraffin wax	IS: 4654-1974 Specification for paraffin wax (first revision).	One Tonne	Rs. 5.00	1976-09-16
7.	Welded low carbon steel gas cylinder for ammonia (anhydrout) gas	IS: 7680-1975 Specification for welded low carbon steel gas cylinder for ammonia (anhydrous) gas	One Cylinder	(i) Rs. 5.00 per unit for the first 5000 units and (ii) Rs. 3.00 per unit for the 5001st units and above.	1976-10-01

[No. CMD/13: 10]

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1976

का०आ० 4735.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे वापस ले लिए गए हैं और अब उन्हें रद्द माना जाए।

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	भारत के राजपत्र अधिसूचना की एस० ओ० संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 2070–1962 आवेग वोल्टता परीक्षण पद्धति	भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखंड (ii) दिनांक 1962-09-29 में एस० ओ० 2976 दिनांक 1962–09–19 के अन्तर्गत प्रकाशित	यह मानक IS : 2071 (भाग 1)–1974 ; IS : 2071 (भाग 2)–1974 और IS : 2071 (भाग 3)–1976 के प्रकाशन के बाद रद्द कर दिया गया है।
2.	IS : 2226–1962 जड़ाऊ प्रकार के मिट्टी पलटने के हल की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 1963–12–28 में एस० ओ० 3590 दिनांक 1963–12–18 के अन्तर्गत प्रकाशित	यह मानक IS : 2192 (भाग 2)–1976 मिट्टी पलटने के हल की विशिष्टि भाग 2 जड़ाऊ प्रकार के प्रकाशन के बाद रद्द कर दिया गया है ।
3.	IS : 3341–1965 डोबी हार्नेस की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखंड ii (दिनांक 1966-04–09 में एस० ओ० 3081 दिनांक 1966–03–25 के अन्तर्गत प्रकाशित	यह मानक IS : 3340–1976 हार्नेस (डोबी और जैकर्ड) की विशिष्टि के प्रकाशन के बाद रद्द कर दिया गया है।

[सं० सी एम डी/13 : 7]

New Delhi, the 26 November, 1976

S.O. 4735.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standards particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S. O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
1	(2)	(3)	(4)
1.	IS: 2070-1962 Method of impulse voltage testing	S.O. 2976 dated 1962-09-19 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1962-09-29	Cancelled in view of publication of IS: 2071 (Part I)-1974; IS: 2071 (Part II)-1974 and IS: 2071 (Part III)-1976.
2.	IS: 2226-1962 Specification for mould-board plough, fixed type.	S.O. 3590 dated 1963-12-18 published in the Gazette of India, Part-II, Section -3, Sub-section (ii) dated 1963-12-28.	Cancelled in view of publication of IS: 2192 (Part II)-1976 Specification for mouldboard plough: Part II Fixed type

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	IS: 3341-1965 Specification for dobby harness.	S.O. 1081 dated 1966-03-25 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1966-04-09.	Cancelled in view of publication of IS: 3340-1976 Specification for harness. (Dobby and Jacquard) (first revision)	

[No. CMD/13 : 7]

का०आ० 4736.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सीएम/एल-3403 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, फर्म की लाइसेंस जारी रखने में रूचि न होने के कारण 1976-08-16 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किये गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीएम/एल-3403 1973-04-30	सर्वश्री संडोज (इंडिया) लि०, संडोज बाग डाकघर, कोलशेट, ठाणे (महाराष्ट्र) कार्यालय : संडोज हाउस, डा, ऐनीबेसंट रोड, वर्ली, बम्बई-18	एन्ड्रिन पायसनीय तेजद्रव	IS : 1310-1974 एन्ड्रिन पायसनीय तेजद्रव की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)

[सं० सीएमडी/55 : 3403 (एपी)]

ए० बी० राव, उपमहानिदेशक

S.O. 4736.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-3403 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1976-08-16 as the Firm is not interested.

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-3403 1973-04-30	M/s Sandoz (India) Ltd, Sandoz Baugh Post Office, Kolshet, Thana (Maharashtra) having their Office at Sandoz House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18.	Endrin EC	IS: 1310-1974 Specification for Endrin Emulsifiable Concentrates (first revision).

[No. CMD/55 : 3403(AP)]

A. B. RAO, Dy. Director General.

पैट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1976

का० आ० 4737.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया परतम से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मौरवी हाउस, जामनगर रोड राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका : चनासमा जिला मेहसाना राज्य : गुजरात

गांव	सर्वेक्षण नं०	क्षेत्र हे०	ए०	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
रनतेज	275	0	09	03
	274	0	22	95
	273	0	35	82
	323/2	0	02	83
	323/1	0	13	91
	324	0	15	84
	340/4	0	15	47
	340/1	0	19	96
	340/2	0	01	48
	340/3	0	13	26
	341	0	02	66
	338	0	54	00
	344	0	12	06
	345	0	33	32
	361	0	14	35
	247/3	0	13	50
	247/2	0	03	60
	247/4	0	18	16
	252	0	56	70
	241	0	26	07
	161	0	08	87
	160	0	08	04
	158	0	14	20
	159	0	01	30
	152/2	0	07	12
	152/1	0	00	20
	151	0	00	37
	56	0	72	62
	55	0	14	11
रूपपुरा कर्णपुरा				
	314	0	06	93
	313	0	06	37
	311	0	22	86
	310	0	13	57
	309	0	17	64
	332	0	30	42
	335	0	25	56
	343	0	32	04
	344	0	11	90
	615	0	15	81
	614	0	14	11
	613	0	02	05
	611	0	16	65
	612	0	12	92
	603	0	25	56
	604	0	16	28
	600	0	12	42
	15	0	11	57
	585	0	20	39
	21	0	14	75
	22	0	22	86
	20	0	00	35
	24	0	21	79
	23	0	00	18
	25	0	00	20
	26/2	0	17	43
	28	0	00	25
	54	0	14	65
	53/4	0	14	14
	46/1	0	05	45
	47	0	11	62
	48	0	16	17
	36/1	0	22	78
असजोल	325	0	09	01
	333	0	20	06
	328	0	25	10
	329	0	08	71
	306/1	0	07	08
	306/2	0	09	62
	306/3	0	11	05
	305	0	14	16
	262	0	24	28
	91/2	0	01	01
	91/3	0	10	62
	91/1	0	02	52
	93/2	0	09	11
	93/3	0	08	60
	95	0	07	58
	96	0	01	52
	97	0	03	55
	92	0	09	11
	48	0	00	10
	140	0	24	28
	139	0	01	75
	142	0	25	29
	143	0	05	06
	145	0	15	18
	144	0	09	72
	168	0	15	18
	169	0	00	60
	167	0	00	75
	170	0	09	11
	164	0	30	35
वनपुर	32	0	16	19
	29	0	49	57
	26	0	11	13
	25	0	83	03
	24	0	20	23
	23	0	12	14

1	2	3	4	5
कणसागर	173/60	0	14	16
	173/61	0	24	28
	173/92	0	14	16
	173/93	0	06	07
	173/99	0	28	33
	173/101	0	25	29
	173/103	0	23	27
	173/105	0	24	28
	173/106	0	16	19
	173/107	0	21	25
	173/109	0	37	43
	173/112	0	26	30
जैतपुर	89	0	08	09
	88	0	19	22
	88/2	0	25	29
	87/बी	0	61	71
	87/12	0	19	21
	87/13	0	18	21
	87/4	0	22	26
	87/3	0	13	15
रमेला	502	0	14	16
	501	0	25	29
	505	0	04	55
	500	0	15	40
	499	0	05	06
	497	0	06	57
	498	0	14	16
	495	0	19	22
	483	0	02	51
	442	0	01	01
	441	0	06	07
	435	0	08	09
	483	0	02	51
	442	0	01	01
	441	0	06	07
	435	0	08	09
	436	0	04	05
	439	0	07	08
	438	0	18	22
	407	0	11	63
	404	0	01	01
	408	0	19	22
	349	0	17	20
	350	0	19	21
	348	0	03	54
	311	0	17	20
	310	0	20	23
	303	0	27	32
	302	0	05	06
	301	0	11	13
	297	0	07	08
	298	0	17	46
	225	0	14	94
	227	0	09	90
	229/2	0	10	80
	229/1	0	09	54
	248/2	0	10	98
	248/1	0	18	00
कनोडा	824	0	00	96
	825	0	21	54
	826	0	15	30
	819	0	14	94
	817	0	19	00
	844	0	13	98
	843	0	11	88
	845	0	00	10
	849	0	00	16
	980	0	05	80
	983	0	23	42
	984	0	01	54
	987	0	18	80
	1003	0	09	36
	1002	0	12	78
	1000	0	09	36
	998	0	05	32
	999	0	01	30
	128	0	25	84
	1073	0	01	88
	1183	0	16	20
	1130	0	26	46
	1133	0	11	88
	1136	0	06	84
	1138/1	0	17	64
	1152	0	32	96
संसार	914	0	18	00
	866	0	09	72
	865	0	10	32
	864/3	0	15	40
	864/2	0	00	40
	863	0	05	48
	870/1	0	03	04
	871/2	0	08	09
	872/2	0	16	38
	855	0	13	40
	854	0	01	28
	853	0	13	20
	878/2	0	03	18
	878/1	0	05	75
	843	0	22	50
	844	0	02	96
	844/1	0	01	28
	838	0	15	40
	837/1	0	19	20
	796	0	13	65
	797	0	00	75
	798/2	0	15	50

1	2	3	4	5
संसार-(जारी)	798/1	0	06	24
	800	0	22	90
	803	0	08	80
	802	0	01	15
	567/1	0	04	60
	567/2	0	09	60
	568	0	07	50
	569	0	14	90
	570	0	19	08
	540	0	09	36
	544	0	23	40
	543	0	16	20
चिनौज	2816	0	18	54
	2819	0	01	95
	2827	0	38	32
	2823	0	01	28
	2826	0	14	24
	2837	0	11	04
	2838	0	25	76
	2839	0	13	76
	576	0	10	12
	577	0	00	50
	574	0	15	18
	566	0	00	15
	568	0	35	41
	573	0	10	12
	934	0	00	05
	935	0	32	35
	936	0	05	65
	924	0	16	19
	925	0	00	50
	923	0	11	13
	922	0	00	76
	921	0	09	11
	920	0	02	02
	902	0	17	20
	900	0	03	04
	899	0	12	14
	898	0	10	12
	897	0	00	10
	801	0	01	51
	800	0	22	26
	799	0	01	51
	798	0	08	09
	796	0	08	60
	793	0	11	63
	720	0	23	27
	717	0	05	06
	714	0	16	19
	724	0	01	01
	713/1	0	00	10
	713	0	16	19
	712/1	0	02	02
	712	0	03	04

1	2	3	4	5
बनौधारावा	100	0	00	30
	709	0	03	84
	101	0	16	32
	80	0	00	64
	81	0	08	80
	82	0	11	36
	83/4	0	00	32
	95	0	05	44
	94	0	11	68
	91/2	0	06	07
	91/1	0	08	12
	22	0	12	40
	20	0	05	06
	19/1	0	02	53
	19/2	0	02	47
	18	0	04	80
	299/1	0	11	34
	300	0	00	32
	302	0	15	00
	303	0	07	00
	304/2	0	00	10
	304/1	0	01	50
	305/1	0	00	32
	305/2	0	04	80
	405/3	0	03	32
	307	0	08	00
	149	0	07	50
	596	0	03	50
	593	0	00	40
	595	0	10	50
	637	0	04	80
	636	0	21	00
	635	0	01	50
	642/1	0	17	80
	642/2	0	00	10
	643/1	0	06	64
	643/2	0	03	32
	647	0	09	16
	646	0	01	64
	648/3	0	03	50
	648/1	0	07	80
	649	0	01	32
	650/1	0	12	00
	650/2	0	04	00
	651	0	10	64
	652/1	0	06	00
मुल्थानिया	13/1	0	05	00
	13/2	0	06	50
	12/1	0	09	00
	20	0	00	64
	22	0	00	80
	21	0	13	00
	34	0	07	50
	23	0	01	32

1	2	3	4	5
मुल्थानिया (जारी)	33	0	12	00
	30	0	01	80
	32	0	07	50
	31	0	08	50
	48	0	15	50
	50	0	04	50
	51/1	0	01	00
	55	0	03	50
	56	0	05	80
	59/1	0	03	50
	59/2	0	02	80
	61	0	05	56
	60	0	04	05
	64	0	13	15
	65	0	10	12
	66	0	03	04
	98	0	06	07
	99	0	02	02
	100	0	08	09
	101	0	24	28
	104	0	01	51
	102	0	00	12
	103	0	12	14
	108	0	05	06
मलाजा	321	0	00	16
	321/1	0	00	20
मालासर	820	0	16	19
	821	0	01	26
	822	0	12	14
	832	0	06	07
	831	0	05	06
	830	0	12	14
	839	0	03	04
	840	0	12	14
	849	0	08	09
	850	0	07	08
	852	0	06	07
	853	0	09	11
	855	0	04	55
	10	0	19	22
	9	0	10	12
	16/2	0	03	04
	8/1	0	05	06
	8/2	0	01	51
	17/2	0	07	08
	25	0	09	08
	24	0	12	14
	23	0	07	08
	20/3	0	06	07
	20/2	0	03	04
	22/2	0	01	01
	21	0	18	21
सैल्वी	224	0	08	09
	223	0	17	20
	241	0	00	10
	224	0	08	09
	223	0	17	20
	241	0	00	10
	242	0	05	06
	222	0	21	25
	215	0	10	12
	214	0	14	16
	213	0	13	15
	135	0	11	13
	136	0	10	62
	134	0	06	07
	133	0	00	05
	138	0	16	19
	107	0	15	18
	109	0	09	60
	105	0	01	50
	104	0	10	12
	110	0	02	02
	93	0	12	14
	94	0	05	06

[सं० 12020/8/76-एल० एण्ड एल/1]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 25th November, 1976

S.O.4737—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the Purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya Koyali/ Mathura Pipeline Project, "Morvi House" Jamnagar road Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Chanasma District : Mehsana State : Gujarat

Village	Survey No.	Extent H.	A.	Sq.M
1	2	3	4	5
Rantej	275	0	09	03
	274	0	22	95
	273	0	35	82

1	2	3	4	5
Rantey (contd.)	323/2	0	02	83
	323/1	0	13	91
	324	0	15	84
	340/4	0	15	47
	340/1	0	19	96
	340/2	0	01	48
	340/3	0	13	26
	341	0	02	66
	338	0	54	00
	344	0	12	06
	345	0	33	32
	361	0	14	35
	247/3	0	13	50
	247/2	0	03	60
	247/4	0	18	16
	252	0	56	70
	241	0	26	07
	161	0	08	87
	160	0	08	04
	158	0	14	20
	159	0	01	30
	152/2	0	07	12
	152/1	0	00	20
	151	0	00	37
	56	0	72	62
	55	0	14	11
Ruppura				
Karanpura	314	0	06	93
	313	0	06	37
	311	0	22	86
	310	0	13	57
	309	0	17	64
	332	0	30	42
	335	0	25	56
	343	0	32	04
	344	0	11	90
	615	0	15	81
	614	0	14	11
	613	0	02	05
	611	0	16	65
	612	0	12	92
	603	0	25	56
	604	0	16	28
	600	0	12	42
	15	0	11	57
	585	0	20	39
	21	0	14	75
	22	0	22	86
	20	0	00	35
	24	0	21	79
	23	0	00	18
	25	0	00	20
	26/2	0	17	43
	28	0	00	25
	54	0	14	65
	53/4	0	14	14
	46/1	0	05	45
	47	0	11	62
	48	0	16	17
	36/1	0	22	78
Asjol	325	0	09	01
	333	0	20	06
	328	0	25	10
	329	0	08	71

1	2	3	4	5
Asloj (cont.d)	306/1	0	07	08
	306/2	0	09	62
	306/3	0	11	05
	305	0	14	16
	262	0	24	28
	91/2	0	01	01
	91/3	0	10	62
	91/1	0	02	52
	93/2	0	09	11
	93/3	0	08	60
	95	0	07	58
	96	0	01	52
	97	0	03	55
	92	0	09	11
	48	0	00	10
	140	0	24	28
	139	0	01	75
	142	0	25	29
	143	0	05	06
	145	0	15	18
	144	0	09	72
	168	0	15	18
	169	0	00	60
	167	0	00	75
	170	0	09	11
	164	0	30	35
Vanpur	32	0	16	19
	29	0	49	57
	26	0	11	13
	25	0	83	03
	24	0	20	23
	23	0	12	14
Karansagar	173/60	0	14	16
	173/61	0	24	28
	173/92	0	14	16
	173/93	0	06	07
	173/99	0	28	33
	173/101	0	25	29
	173/103	0	23	27
	173/105	0	24	28
	173/106	0	16	19
	173/107	0	21	25
	173/109	0	37	43
	173/112	0	26	30
Jetpur	89	0	08	09
	88	0	19	22
	88/2	0	25	29
	87/B	0	61	71
	87/12	0	18	21
	87/13	0	18	21
	87/4	0	22	26
	87/3	0	13	51
Ranela	502	0	14	16
	501	0	25	29
	505	0	04	55
	500	0	15	40
	499	0	05	06
	497	0	06	57
	498	0	14	16
	495	0	19	28
	483	0	02	51
	442	0	01	01
	441	0	06	07
	435	0	08	09

1	2	3	4	5
Ranela (contd.)	436	0	04	05
	439	0	07	08
	438	0	19	22
	407	0	11	63
	404	0	01	01
	408	0	19	22
	349	0	17	20
	350	0	18	21
	348	0	03	54
	311	0	17	20
	310	0	20	23
	303	0	27	32
	302	0	05	06
	301	0	11	13
	297	0	07	08
	298	0	17	46
	225	0	14	94
	227	0	09	90
	229/2	0	10	80
	229/1	0	09	54
	248/2	0	10	98
	248/1	0	18	00
Kanoda . . .	824	0	00	96
	825	0	21	54
	826	0	15	30
	819	0	14	94
	817	0	19	00
	844	0	13	98
	843	0	11	88
	845	0	00	10
	846	0	18	00
	852	0	14	76
	851	0	11	88
	850	0	18	02
	849	0	00	16
	980	0	05	80
	983	0	23	42
	984	0	01	54
	987	0	18	80
	1003	0	09	36
	1002	0	12	78
	1000	0	09	36
	998	0	05	32
	999	0	01	30
	128	0	25	84
	1073	0	01	88
	1183	0	16	20
	1130	0	26	46
	1133	0	11	88
	1136	0	06	84
	1138/1	0	47	64
	1152	0	32	96
Sunsar	914	0	18	00
	866	0	09	72
	865	0	10	32
	864/3	0	15	40
	864/2	0	00	40
	863	0	05	48
	870/1	0	03	04
	871/2	0	08	09
	872/2	0	16	38

1	2	3	4	5
Sunsar (contd.)	855	0	13	40
	854	0	01	28
	853	0	13	20
	878/2	0	03	18
	878/1	0	05	75
	843	0	22	50
	844	0	02	96
	844/1	0	01	28
	838	0	15	40
	837/1	0	19	20
	796	0	13	65
	797	0	00	75
	798/2	0	15	50
	798/1	0	06	24
	800	0	22	90
	803	0	08	80
	802	0	01	15
	567/1	0	04	60
	567/2	0	09	60
	568	0	07	50
	569	0	14	90
	570	0	09	08
	540	0	09	36
	544	0	23	40
	543	0	16	20
Dhinoj . . .	2816	0	18	54
	2819	0	01	95
	2827	0	38	32
	2823	0	01	28
	2826	0	14	24
	2837	0	11	04
	2838	0	25	76
	2839	0	13	76
	576	0	10	12
	577	0	00	50
	574	0	15	18
	566	0	00	15
	568	0	35	41
	573	0	10	12
	934	0	00	05
	935	0	32	35
	936	0	05	65
	924	0	16	19
	925	0	00	50
	923	0	11	13
	922	0	00	76
	921	0	09	11
	920	0	02	02
	902	0	17	20
	900	0	03	04
	899	0	12	14
	898	0	10	12
	897	0	00	10
	801	0	01	51
	800	0	22	26
	799	0	01	51
	798	0	08	09
	796	0	08	60
	793	0	11	63
	720	0	23	27
	717	0	05	06

1	2	3	4	5
Dhinoj (contd.)	714	0	16	19
	724	0	01	01
	713/1	0	00	10
	713	0	16	19
	712/1	0	02	02
	712	0	03	04
Danodarada	100	0	00	30
	709	0	03	84
	101	0	16	32
	80	0	00	64
	81	0	08	80
	82	0	11	36
	83/4	0	00	32
	95	0	05	44
	94	0	11	68
	91/2	0	06	07
	91/1	0	08	12
	22	0	12	40
	20	0	05	06
	19/1	0	02	53
	19/2	0	02	47
	18	0	04	80
	299/1	0	11	34
	300	0	00	32
	302	0	15	00
	303	0	07	00
	304/2	0	00	10
	304/1	0	01	50
	305/1	0	00	32
	305/2	0	04	80
	305/3	0	03	32
	307	0	08	00
	149	0	07	50
	596	0	03	50
	593	0	00	40
	595	0	10	50
	637	0	04	80
	636	0	21	00
	635	0	01	50
	642/1	0	17	80
	642/2	0	00	10
	643/1	0	06	64
	643/2	0	03	32
	647	0	09	16
	646	0	01	64
	648/3	0	03	50
	648/1	0	07	80
	649	0	01	32
	650/1	0	12	00
	650/2	0	04	00
	651	0	10	64
	652/1	0	06	00
Multhania	13/1	0	05	00
	13/2	0	06	50
	12/1	0	09	00
	20	0	00	64
	22	0	00	80
	21	0	13	00
	34	0	07	50
	23	0	01	32
	33	0	12	00
	30	0	01	80
	32	0	07	50
	31	0	08	50
Multhania (contd.)	48	0	15	50
	50	0	04	50
	51/1	0	01	00
	55	0	03	50
	56	0	05	80
	59/1	0	03	50
	59/2	0	02	80
	61	0	05	56
	60	0	04	05
	64	0	13	15
	65	0	10	12
	66	0	03	04
	98	0	06	07
	99	0	02	02
	100	0	08	09
	101	0	24	28
	104	0	01	51
	102	0	00	12
	103	0	12	14
	108	0	05	06
Lanava	321	0	00	16
	321/1	0	00	20
Palasar	820	0	16	19
	821	0	01	26
	822	0	12	14
	832	0	06	07
	831	0	05	06
	830	0	12	14
	839	0	03	01
	840	0	12	14
	849	0	08	09
	850	0	07	08
	852	0	06	07
	853	0	09	11
	855	0	04	55
	10	0	19	22
	9	0	10	12
	16/2	0	03	04
	8/1	0	05	06
	8/2	0	01	51
	17/2	0	07	08
	25	0	08	09
	24	0	12	14
	23	0	07	08
	20/3	0	06	07
	20/2	0	03	04
	22/2	0	01	01
	21	0	18	21
Selavi	224	0	08	09
	223	0	17	20
	241	0	00	10
	242	0	05	06
	222	0	21	25
	215	0	10	12
	214	0	14	16
	213	0	13	15
	135	0	11	13
	136	0	10	62
	134	0	06	07
	133	0	00	05

1	2	3	4	5
Selavi (contd)	138	0	16	19
	107	0	15	18
	109	0	09	60
	105	0	01	50
	104	0	10	12
	110	0	02	02
	93	0	12	14
	94	0	05	06

[No. 12020/8/76-L & L/I]

का० आ० 4738.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है,

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मोरबी हाउस, जामनगर रोड, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तालुका : पत्तन जिला : मेहसाना राज्य : गुजरात

गांव	सर्वेक्षण नं०	हे०	ए०	वर्ग मीटर
मनंद	2230	0	24	28
	2231	0	00	10
	2289	0	13	14
	2288	0	10	50
	2287	0	05	20
	2286	0	17	90
	2285	0	01	50
	2284	0	13	15
	2283	0	05	06
	2282	0	09	11
	2281	0	22	26
	2280	0	14	16
	2273	0	16	19
	2274	0	08	09
	2211/2	0	00	05
	2275	0	00	15
	2109/2	0	04	05
मनंद—जारी	2109/1	0	00	35
	2110	0	11	13
	2108	0	17	20
	2059	0	24	28
	2058	0	01	51
	2125	0	08	09
	2126	0	12	14
	2126/1	0	12	14
	2042	0	08	09
	2041	0	08	09
	2043	0	15	18
	2044	0	16	19
	2036	0	06	07
	2008	0	20	23
	2009	0	00	15
	2007	0	10	12
	1853	0	08	09
	1852	0	05	06
	1854/1	0	06	07
	1854/2	0	16	19
	1849	0	07	60
	1848	0	15	18
	1832	0	12	14
	1833	0	07	08
	1835	0	21	25
	1836	0	01	01
	1773	0	11	13
	1770	0	16	19
	1769	0	04	04
	1776/2	0	04	55
	1768	0	11	13
	1759	0	12	14
	1758	0	01	01
	1743	0	10	12
	1741	0	13	15
	1740	0	00	75
	1649	0	15	18
	1650	0	09	11
	1651	0	10	62
	1609	0	08	09
	1610	0	02	02
	1608	0	10	62
	1606	0	13	15
	1605	0	13	15
	1665	0	17	20
	1663	0	03	04
	1667	0	11	13
	1668	0	01	01
	1712	0	12	14
धभादी	480	0	00	15
	481	0	26	00
	482	0	12	14
	483	0	19	22
	484	0	00	50
	614	0	08	09

1	2	3	4	5
वमादी—जारी	615	0	04	05
	613	0	08	09
	554	0	21	25
	555	0	02	52
	552	0	15	18
	556	0	31	36
	543	0	02	52
	542	0	13	15
	541	0	09	11
	563	0	16	19
	348/2	0	03	04
	348/1	0	05	06
	347	0	15	18
	346	0	08	59
	335	0	25	29
	336	0	11	63
	340	0	16	19
	338	0	00	10
	339	0	11	25
	277	0	09	61
	278	0	15	18
	280	0	14	16
	281	0	10	12
	272	0	09	61
	271	0	13	15
	270	0	28	33
	283	0	01	51
रुवाची	258	0	17	20
	257	0	03	57
	260	0	16	12
	261	0	12	32
	277	0	07	95
	276	0	08	05
	291	0	13	15
	292	0	00	35
	293/3	0	02	70
	293/1	0	03	71
	293/2	0	17	05
	295/2	0	09	73
	295/1	0	00	65
	296/1	0	09	93
	310	0	04	68
	311/3	0	06	30
	311/2	0	04	90
	311/1	0	04	20
	312/1	0	11	93
	312/2	0	00	37
	314	0	09	76
	381	0	79	62
कानी	167	0	05	14
	166	0	20	77
	164	0	11	90
	165/4	0	06	72
	162	0	18	40

1	2	3	4	5
कानी—जारी	161	0	03	60
	160	0	00	12
	130	0	02	64
	131	0	12	03
	132/1	0	04	25
	132/2	0	11	18
	127	0	02	02
	133/2	0	20	60
	105/5	0	00	85
	105/4	0	10	15
	105/3	0	07	38
	104	0	02	02
	97	0	09	57
	99	0	08	55
	83	0	13	08
	84	0	13	76
	78	0	13	12
	76/1	0	12	10
	76/2	0	10	95
	75	0	10	70

[सं० 12020/8/76-एल० एंड एल-II]

टी० पी० सुब्रह्मनियम, अवर सचिव

S.O. 4738.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation]Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "Morvi House" Jamnagar road, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Patan	District: Mehsana	State: Gujarat		
Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M
Munund	2230	0	24	28
	2231	0	00	10
	2289	0	13	14
	2288	0	10	50

1	2	3	4	5
Munund (contd.)	2287	0	05	20
	2286	0	17	90
	2285	0	01	50
	2284	0	13	15
	2283	0	05	06
	2282	0	09	11
	2281	0	22	26
	2280	0	14	16
	2273	0	16	19
	2274	0	08	09
	2211/2	0	00	05
	2275	0	00	15
	2109/2	0	04	05
	2109/1	0	00	35
	2110	0	11	13
	2108	0	17	20
	2059	0	24	28
	2058	0	01	51
	2125	0	08	09
	2126	0	12	14
	2126/1	0	12	14
	2042	0	08	09
	2041	0	08	09
	2043	0	15	18
	2044	0	16	19
	2036	0	06	07
	2008	0	20	23
	2009	0	00	15
	2007	0	10	12
	1853	0	08	09
	1852	0	05	06
	1854/1	0	06	07
	1854/2	0	16	19
	1849	0	07	60
	1848	0	15	18
	1832	0	12	14
	1833	0	07	08
	1835	0	21	25
	1836	0	01	01
	1773	0	11	13
	1770	0	16	19
	1769	0	04	04
	1776/2	0	04	55
	1768	0	11	13
	1759	0	12	14
	1758	0	01	01
	1743	0	10	12
	1741	0	13	15
	1740	0	0	75
	1649	0	15	18
	1650	0	09	11
	1651	0	10	62
	1609	0	08	09
	1610	0	02	02
	1608	0	10	62
	1606	0	13	15
	1605	0	13	15
	1665	0	17	20
	1663	0	03	04
	1667	0	11	13
	1668	0	01	01
	1712	0	12	14

1	2	3	4	5
Dabhadi	480	0	03	15
	481	0	26	00
	482	0	12	14
	483	0	19	22
	484	0	00	50
	614	0	08	09
	615	0	04	05
	613	0	08	09
	554	0	21	25
	555	0	02	52
	552	0	15	18
	556	0	31	36
	543	0	02	52
	542	0	13	15
	541	0	09	11
	563	0	16	19
	348/2	0	03	04
	348/1	0	05	06
	347	0	15	18
	346	0	08	59
	335	0	25	29
	336	0	11	63
	340	0	16	19
	338	0	00	10
	339	0	11	25
	277	0	09	61
	278	0	15	18
	280	0	14	16
	281	0	10	12
	272	0	09	61
	271	0	13	15
	270	0	28	33
	283	0	01	51
Ruvavi	258	0	17	20
	257	0	03	57
	260	0	16	12
	261	0	12	32
	277	0	07	95
	276	0	08	05
	291	0	13	15
	292	0	00	35
	293/3	0	02	70
	293/1	0	03	71
	293/2	0	17	05
	295/2	0	09	73
	295/1	0	00	65
	296/1	0	09	93
	310	0	04	68
	311/3	0	06	30
	311/2	0	04	90
	311/1	04	04	20
	312/1	0	11	93
	312/2	0	00	37
	314	0	09	76
	381	0	79	62
Kani	167	0	05	14
	166	0	20	77
	164	0	11	90
	165/4	0	06	72
	162	0	18	40
	161	0	03	60
	160	0	00	12
	130	0	02	64
	131	0	12	03
	132/1	0	04	25

1	2	3	4	5
Kani (contd.)	132/2	0	11	18
	127	0	02	02
	133/2	0	20	60
	105/5	0	00	85
	105/4	0	10	15
	105/3	0	07	38
	104	0	02	02
	97	0	09	57
	99	0	08	55
	83	0	13	08
	84	0	13	76
	78	0	13	12
	76/1	0	12	10
	76/2	0	10	95
	75	0	10	70

[No. 12020/8/76-L&L/II]

T.P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1976

का०आ० 4739.—यतः औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ix) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने श्री आर० वी० पाणि, औषधि नियंत्रक, उड़ीसा और श्री एम० आर० शास्त्री, निदेशक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, गुजरात को 26 मई, 1976 से औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है ;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (x) के अनुसरण में भारत की भेषजी परिषद् की कार्यपालिका समिति ने श्री एस० एन० वर्मा, भैषजिक विज्ञान के प्रोफेसर और अध्यक्ष, सागर विश्वविद्यालय, सागर को 26 मई, 1976 से औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (xi) के अनुसरण में भारत की आयुर्विज्ञान परिषद् ने डा० के० पी० गणेशन, आयुर्विज्ञान प्रोफेसर, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मंगलौर को 10 सितम्बर, 1976 से औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (xii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने डा० परविन्दर सिंह, महाप्रबन्धक, मेसर्स रण बक्सी लेबोरेटरीज, दिल्ली को 26 मई, 1976 से औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (xiii) के अनुसरण में भारतीय आयुर्विज्ञान अन्वेषण परिषद् ने डा० यू० के० सेठ, भेषजिक प्रोफेसर, सेठ एस० जी० मेडिकल कालेज, परेल, मुम्बई को 26 मई, 1976 से औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (xiv) के अनुसरण में, भारतीय आयुर्विज्ञान संगम ने डा० एम० ए० पानवाला, 3 नीलकण्ठ पार्क, राजाबाड़ी, बम्बई को 26 मई, 1976 से औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (xv) के अनुसरण में भारतीय भेषजिक संगम ने श्री के० जे० दिवातिया, प्रबन्ध निदेशक, साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड, वादीवाड़ी, बड़ौदा को 26 मई, 1976 से औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (vxi) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने डा० रविन्दर नाथ आध्या, सरकारी विश्लेषक, औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, कलकत्ता को और श्री वी० जे० टामस, सरकारी विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम को 26 मई, 1976 से औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि प्रो० एस० एन० शर्मा, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1772, तारीख 26 मई, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) 'धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (9) के अधीन नाम निर्दिष्ट' शीर्षक के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् —

'1. श्री आर० वी० पाणि, औषधि नियंत्रक, उड़ीसा ।

2. श्री एम० आर० शास्त्री, निदेशक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, गुजरात ।'

(ii) 'धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (11) के अधीन निर्वाचित' शीर्षक के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

'डा० के० पी० गणेशन्, आयुर्विज्ञान प्रोफेसर, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मंगलौर' ।

(iii) 'धारा 5 की उपधारा (2) खण्ड (12) के अधीन नाम निर्दिष्ट' शीर्षक के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

'डा० परविन्दर सिंह, महाप्रबन्धक, मेसर्स रण बक्सी लेबोरेटरीज, दिल्ली' ।

(iv) 'धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (13) के अधीन निर्वाचित' शीर्षक के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

'डा० यू० के० सेठ, भेषजिक प्रोफेसर, सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, परेल, मुम्बई' ।

(v) 'धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (14) के अधीन निर्वाचित' शीर्षक के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

'डा० एम० ए० पानवाला, 3 नीलकण्ठ पार्क, घाट कोपर, पूर्वी डाकघर, राजाबाड़ी, बम्बई ।'

(vi) 'धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (15) के अधीन निर्वाचित' शीर्षक के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

'डा० के० जे० दिवातिया, प्रबन्ध निदेशक, साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स 31, वादीवाड़ी, बड़ौदा ।'

(vii) 'धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (16) के अधीन नामनिर्दिष्ट' शीर्षक के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

'1. डा० रबिन्दर नाथ आध्या, सरकारी विश्लेषक औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, कलकत्ता;

2. श्री वी० जे० टामस, सरकारी विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम ।'

[सं० X 19012/3/76-डी० एण्ड एम० एस०]

जी० पंचापकेशन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 30th November, 1976

S.O. 4739.—Whereas in pursuance of clause (ix) of sub-section 2 of section 5 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) the Central Government has nominated Shri R. B. Pany, Drugs Controller, Orissa and Shri M. R. Shastri, Director, Drugs Control Administration, Gujarat as members of the Drugs Technical Advisory Board, with effect from the 26th May, 1976;

And whereas in pursuance of clause (x) of sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Executive Committee of the Pharmacy Council of India has elected Shri S. N. Sharma, Professor and Head of Pharmaceutical Sciences, University of Saugar, Sagar as a member of the Drugs Technical Advisory Board, with effect from the 26th May, 1976;

And whereas in pursuance of clause (xi) of sub-section (2) of section 5 of the said Act the Medical Council of India has elected Dr. K. P. Ganesan Professor of Medicine, Kasturba Medical College, Mangalore, as a member of the Drugs Technical Advisory Board, with effect from the 10th September, 1976;

And whereas in pursuance of clause (xii) of sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government has nominated Dr. Parvinder Singh, General Manager, M/s. Ranbaxy Laboratories, Delhi, as a member of the Drugs Technical Advisory Board, with effect from the 26th May, 1976;

And whereas in pursuance of clause (xiii) of sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Indian Council of Medical Research has elected Dr. U. K. Seth, Professor of Pharmacology, Seth S. G. Medical College, Parel, Bombay, as a member of the Drugs Technical Advisory Board, with effect from the 26th May, 1976;

And whereas in pursuance of clause (xiv) of sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Indian Medical Association has elected Dr. M. A. Panwala, 3, Nilkanth Park, Rajawadi, Bombay, as a member of the Drugs Technical Advisory Board, with effect from the 26th May, 1976;

And whereas in pursuance of clause (xv) of sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Indian Pharmaceutical Association has elected Shri K. J. Divatia, Managing Director, Sarabhai Chemicals Ltd., Wadiwadi, Baroda, as a member of the Drugs Technical Advisory Board, with effect from the 26th May, 1976;

And whereas in pursuance of clause (xvi) of sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government has nominated Dr. Rabindra Nath Adhya, Government Analyst, Drugs Control Laboratory, Calcutta, and Shri V. J. Thomas, Government Analyst, Drugs Testing Laboratory, Trivandrum, as members of the Drugs Technical Advisory Board, with effect from 26th May, 1976;

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (1) and sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby directs that Prof. S. N. Sharma shall continue to be a member of the Drugs Technical Advisory Board and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No. S.O. 1772, dated the 26th May, 1973, namely:—

In the said notification,—

(i) under the head "Nominated under clause (ix) of sub-section 2 of section 5", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"1. Shri R. B. Pany, Drugs Controller, Orissa.

2. Shri M. R. Shastri, Director, Drugs Control Administration, Gujarat.";

(ii) under the head "Elected under clause (xi) of sub-section (2) of section 5", for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. K. P. Ganesan, Professor of Medicine, Kasturba Medical College, Mangalore";

(iii) under the head "Nominated under clause (xii) of sub-section 2 of the section 5", for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely :—

"Dr. Parvinder Singh, General Manager, M/s. Ranbaxy Laboratories, Delhi.";

(iv) under the head "Elected under clause (xiii) of sub-section 2 of the section 5", for the existing entry, the following entry shall be substituted; namely:—

"Dr. U. K. Seth, Professor of Pharmacology, Seth G. S. Medical College, Parel, Bombay.";

(v) under the head "Elected under clause (xiv) of sub-section 2 of section 5", for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

Dr. M. A. Panwala, 3, Nilkanth Park, Ghatkopar (East) P. O. Rajawadi, Bombay.";

(vi) under the head "Elected under clause (xv) of sub-section (2) of section 5", for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Dr. K. J. Divetia Managing Director, Sarabhai Chemicals, Ltd., Post Box 31, Wadiwadi Baroda.";

(vii) under the head "Nominated under clause (xvi) of sub-section (2) of section 5", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"1. Dr. Rabindra Nath Adhya, Government Analyst, Drugs Control Laboratory, Calcutta.

2. Shri V. J. Thomas, Government Analyst, Drugs Testing Laboratory, Trivandrum.".

[No. X. 19012/3/76-D&MS]
G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1976

का० आ० 4740.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम मांस खाद्य उत्पाद (संशोधन) आदेश 1976 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा

2. मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 में, खण्ड 14 में,—

(i) उपखण्ड (1) में, "कोई अधिकारी" शब्दों के पश्चात् "जो विपणन और निरीक्षण निदेशालय के सहायक विपणन अधिकारी की पंक्ति से कम का न हो," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपखण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की 2) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस खण्ड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।"

[सं० फा० 16-26/73-ए० एम (भाग 2)]

ए० के० अग्रवाल, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 18th November, 1976

S.O. 4740.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Meat Food Products Order, 1973, namely :—

1. (1) This Order may be called the Meat Food Products (Amendment) Order, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Meat Food Products Order, 1973, in clause 14,—

(1) in sub-clause (1), after the words "any officer", the words "not below the rank of Assistant Marketing Officer of the Directorate of Marketing and Inspection" shall be inserted;

(2) after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(3) The provisions of the code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)), relating to search and seizure shall, so far as may be apply to searches and seizures under this clause."

[No. F. 16-26/73-AM(Pt. II)]
A. K. AGARWAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1976

का०आ० 4741.—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित वस्तु को लागू होंगे, अर्थात् :—

"टैपियोका साबूदाना"

[सं० 13-15/75-प्रणा०]

आर० एन० बख्शी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th November, 1976

S.O. 4741.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby declares that the provisions of the said Act shall apply to the following articles namely :—

"Tapioca Sago".

[No. F. 13-15/75-AM]
R. N. BAKSHI, Under Secy.

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1976

का०आ० 4742.—यतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया है जो कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं ।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय की उक्त अधिनियम की धारा 12-ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है ।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37), यथा अद्यतन संशोधित, की धारा 12 एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन किस पद पर स्थायी हैं?	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के किस पद पर थे?	भारतीय खाद्य निगम को स्थानांतर की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री आर० एल० अहलुवालिया	सत्यापन निरीक्षक	मुख्य सत्यापन निरीक्षक	3-6-69
2.	श्री विजयपाल सिंह	गुण निरीक्षक	गुण निरीक्षक	1-3-69
3.	श्री शोबरन सिंह	डस्टिंग आपरेटर	डस्टिंग आपरेटर	1-3-69
4.	श्री गोविन्द सिंह	—वही—	—वही—	1-3-69
5.	श्री विजय सिंह	—वही—	—वही—	1-3-69
6.	श्री आर०आर० मागर	—वही—	—वही—	1-3-69
7.	श्री एम०आर० कदम	—वही—	—वही—	1-3-69
8.	श्री के० बी० सिंह		—वही—	1-3-69
9.	श्री डी० बी० मागरे		गोदाम क्लर्क	1-3-69

[सं० 52/7/74—एफ० सी० 3 (खंड 8)]

बख्शी राम, उप सचिव

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 24th November, 1976

S.O. 4742.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directors of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India;

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorates of the Food, the Procurement Directorates and the Pay and Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the circular of the Central Governmet dated the 16th April, 1971, intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the provisio to sub section (1) of section 12A of the said Act ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), as amended upto date, the Central Government hereby transfers the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them:—

S.No	Name of the Officer/Employee	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer.	Date of transfer to the Food Corporation of India.
1.	Shri R.L. Ahluwalia	Verification Inspector	Chief Verification Inspector	3-6-69
2.	Shri Vijai Pal Singh	Quality Inspector	Quality Inspector	1-3-69
3.	Shri Shobran Singh	Dusting Operator	Dusting Operator	1-3-69
4.	Shri Govind Singh	Dusting Operator	Dusting Operator	1-3-69
5.	Shri Vijay Singh	Dusting Operator	Dusting Operator	1-3-69
6.	Shri R.R. Magar	Dusting Operator	Dusting Operator	1-3-69
7.	Shri N.R. Kadam	Dusting Operator	Dusting Operator	1-3-69
8.	Shri K.B. Singh		Dusting Operator	1-3-69
9.	Shri D.B. Nagre		Godown Clerk	1-3-69

[No. 52/7/74-FCIII(Vol. VIII)]
BAKSHI RAM, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1976

(व्यापार पोत)

का०आ० 4743.—व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 283 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की 19 जनवरी, 1973 की अधिसूचना संख्या सा० आ० 522 का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट देशों ने तथा उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट उन क्षेत्रों ने जिनमें उक्त संगमन का विस्तार हुआ है, प्रत्येक देश अथवा क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, के सामने स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट तारीखों से सुरक्षा संगमन (अर्थात् लन्दन में 17 जून, 1960 को हस्ताक्षर किए गए "समुद्र में जीवन सुरक्षा संगमन" को स्वीकार कर लिया है :—

सारणी

सुरक्षा संगमन को स्वीकार करने वाले देश अथवा उक्त संगमन का विस्तार पाने वाले क्षेत्र का नाम	स्वीकार करने या विस्तार पाने की तिथि
(1)	(2)
1. हैटी	17 मार्च, 1961
2. नार्वे	23 अगस्त, 1961
3. फ्रांस	16 अक्तूबर, 1961
4. वियतनाम	8 जनवरी, 1962
5. घाना	22 मार्च, 1962
6. पीरू	25 जुलाई, 1962
7. संयुक्त राज्य अमरीका	2 अगस्त, 1962
8. माडागास्कर	13 सितम्बर, 1962
9. मोरक्को	28 नवम्बर, 1962
10. स्पेन	22 जनवरी, 1963
11. यूनान	13 फरवरी, 1963
12. जापान	23 अप्रैल, 1963
13. ट्यूनिसिया	20 मई, 1963
14. क्यूबा	22 अगस्त, 1963
15. पारागुए	11 सितम्बर, 1963
16. अल्जीरिया	20 जनवरी, 1964
17. लाइबेरिया	26 मई, 1964
18. यूनाइटिड किंगडम	11 जून, 1964
19. नीदरलैण्ड	16 अक्तूबर, 1964
20. डेन्मार्क	1 दिसम्बर, 1964
21. आइसलैण्ड	11 दिसम्बर, 1964
22. यूगोस्लाविया	23 फरवरी, 1965
23. साउदी अरबिया	3 मई, 1965
24. फिनलैण्ड	11 मई, 1965
25. कुवैत	14 मई, 1965
26. कोरिया गणराज्य	21 मई, 1965
27. जर्मन संघ गणराज्य	25 मई, 1965
28. कनाडा	26 मई, 1965
29. बर्मा	12 जुलाई, 1965
30. साइप्रेस	26 जुलाई, 1965
31. मिस्र	27 जुलाई, 1965
32. यू०एस०एस०आर०	4 अगस्त, 1965
33. फिलिपाइन्स	11 अगस्त, 1965
34. मलेशिया	16 अगस्त, 1965
35. इजराइल	5 अक्तूबर, 1965
36. पानामा	12 अक्तूबर, 1965
37. आइवरी कोस्ट	2 नवम्बर, 1965
38. नाइजीरिया	30 नवम्बर, 1965
39. स्वीडन	23 दिसम्बर, 1965
40. स्वीट्जरलैण्ड	12 जनवरी, 1966
41. बेल्जियम	10 फरवरी, 1966
42. न्यूजीलैण्ड	14 फरवरी, 1966

1	2
43. पाकिस्तान	24 फरवरी, 1966
44. भारतवर्ष	28 फरवरी, 1966
45. लेबनान	27 अप्रैल, 1966
46. अर्जेनटाइना	27 अप्रैल, 1966
47. पोलैण्ड	29 अप्रैल, 1966
48. इटली	26 मई, 1966
49. ईरान	31 मई, 1966
50. टर्की	2 जून, 1966
51. पुर्तगाल	14 जून, 1966
52. मक्सीको	22 जून, 1966
53. ट्रिनिदाद और टोबागो	6 सितम्बर, 1966
54. घिल्ली	7 सितम्बर, 1966
55. इण्डोनेशिया	26 अक्तूबर, 1966
56. गाम्बिया	1 नवम्बर, 1966
57. रूमानिया	12 दिसम्बर, 1966
58. आयरलैण्ड	14 फरवरी, 1967
59. ब्राजील	8 मार्च, 1967
60. सोमालिया	30 मार्च, 1967
61. चैकोस्लोवाकिया	5 जुलाई, 1967
62. निकारागुआ	9 अक्तूबर, 1967
63. बल्गारिया	16 अक्तूबर, 1967
64. मारितानिया	4 दिसम्बर, 1967
65. साउथ अफ्रीका	13 दिसम्बर, 1967
66. आस्ट्रेलिया	20 दिसम्बर, 1967
67. मालदीव्ज	29 जनवरी, 1968
68. जमैका	22 फरवरी, 1968
69. जैरे	20 मई, 1968
70. गुआनिया	5 सितम्बर, 1968
71. यूरुगुआ	19 सितम्बर, 1968
72. सीरियन अरब गणराज्य	24 दिसम्बर, 1968
73. वेनेजुएला	23 जनवरी, 1969
74. सिंगापुर	12 फरवरी, 1969
75. हण्डेरास	18 फरवरी, 1969
76. डेमोक्रेटिक यमन	20 मई, 1969
77. नौरु	19 जनवरी, 1970
78. हंगरी	24 मार्च, 1970
79. मोनाको	25 मार्च, 1970
80. सेनेगल	9 अप्रैल, 1970
81. जाम्बिया	2 सितम्बर, 1970
82. डेमोक्रेटिक कामपुचिया	24 नवम्बर, 1970
83. इक्वेटोरियल गुआनिया	3 मार्च, 1972
84. आस्ट्रिया	4 अगस्त, 1972
85. फिजी	15 अगस्त, 1972
86. लिबियन अरब गणराज्य	10 जनवरी, 1973
87. गैबन	3 सितम्बर, 1973
88. चीन	5 अक्तूबर, 1973
89. श्रीलंका	10 मई, 1974
90 इक्युएडर	30 जून 1975
91. ओमान	20 अगस्त, 1975
92. केन्या	12 सितम्बर, 1975
93. पापुआ न्यू गुआनिया	18 मई, 1976
94. बाहामास	22 जुलाई, 1976

संगमन निम्नलिखित क्षेत्रों में भी लागू होता है :—

नीदरलैण्ड्स एन्टील्स	16 अक्तूबर, 1964
गुआम, पेरटो रिको, विर्जिन आइलैण्ड्स	26 मई, 1965
हांगकांग	7 दिसम्बर, 1965
बेरमुडा	27 मई, 1975
केनाल जोन, अमरिकन सामोआ ट्रस्ट टेरीटरीज आफ दि पैसिफिक आइलैण्ड्स	9 सितम्बर, 1975
मिडवे आइलैण्ड्स, वेक आइलैण्ड जोन्स्टन आइलैण्ड	18 मार्च, 1976

[सं० 11-एम टी ओ (26)/76-एम ए]

राम तिलक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th November, 1976

MERCHANT SHIPPING

S.O. 4743.—In exercise of the powers conferred by section 283 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 522, dated the 19th January, 1973, the Central Government hereby declares that the countries specified in column 1 of the Table below have accepted the Safety Convention (namely, the Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on the 17th Day of June, 1960), and the territories specified in the said column to which the said Convention extends, with effect from the dates indicated against each country or the territory, as the case may be, in column 2 thereof.

TABLE

Name of the country which has accepted the Safety Convention or the territory to which the said Convention extends.	Date of acceptance or extension.
1	2
1. Haiti	17 March 1961
2. Norway	23 August 1961
3. France	16 October 1961
4. Viet-Nam	8 January 1962
5. Ghana	22 March 1962
6. Peru	25 July 1962
7. United States	2 August 1962
8. Madagascar	13 September 1962
9. Morocco	28 November 1962
10. Spain	22 January 1963
11. Greece	13 February 1963
12. Japan	23 April 1963
13. Tunisia	20 May 1963
14. Guba	22 August 1963
15. Paraguay	11 September 1963
16. Algeria	20 January 1964
17. Liberia	26 May 1964
18. United Kingdom	11 June 1964
19. Netherlands	16 October 1964
20. Denmark	1 December 1964
21. Iceland	11 December 1964
22. Yugoslavia	23 February 1965

1	2
23. Saudi Arabia	3 May 1965
24. Finland	11 May 1965
25. Kuwait	14 May 1965
26. Republic of Korea	21 May 1965
27. Germany, Federal Republic	25 May 1965
28. Canada	26 May 1965
29. Burma	12 July 1965
30. Cyprus	26 July 1965
31. Egypt	27 July 1965
32. USSR	4 August 1965
33. Philippines	11 August 1965
34. Malaysia	16 August 1965
35. Israel	5 October 1965
36. Panama	12 October 1965
37. Ivory Coast	2 November 1965
38. Nigeria	30 November 1965
39. Sweden	23 December 1965
40. Switzerland	12 January 1966
41. Belgium	10 February 1966
42. New Zealand	14 February 1966
43. Pakistan	24 February 1966
44. India	28 February 1966
45. Lebanon	27 April 1966
46. Argentina	27 April 1966
47. Poland	29 April 1966
48. Italy	26 May 1966
49. Iran	31 May 1966
50. Turkey	2 June 1966
51. Portugal	14 June 1966
52. Mexico	22 June 1966
53. Trinidad and Tobago	6 September 1966
54. Chile	7 September 1966
55. Indonesia	26 October 1966
56. Gambia	1 November 1766
57. Romania	12 December 1766
58. Ireland	14 February 1967
59. Brazil	8 March 1967
60. Somalia	30 March 1967
61. Czechoslovakia	5 July 1967
62. Nicaragua	9 October 1967
63. Bulgaria	16 October 1967
64. Mauritania	4 December 1967
65. South Africa	13 Ddecember 1967
66. Australia	20 December 1967
67. Maldivas	29 January 1968
68. Jamaica	22 February 1968
69. Zaire	20 May 1968
70. Guinea	5 September 1968
71. Uruguay	19 September 1968
72. Syrian Arab Republic	24 December 1968
73. Venezuela	23 January 1969
74. Singapore	12 February 1969
75. Honduras	18 February 1969
76. Democratic Yemen	20 May 1969
77. Nauru	19 January 1970
78. Hungary	24 March 1970
79. Moonaco	25 March 1970
80. Senegal	9 April 1970
81. Zambia	2 September 1970
82. Democratic Kamouchea	24 November 1970
83. Equatorial Guinea	3 March 1972
84. Austria	4 August 1972
85. Fiji	15 August 1972
86. Libyan Arab Republic	10 Januaray 1973
87. Gabon	3 September 1973
88. China	5 October 1973
89. Sri Lanka	10 May 1974
90. Ecuador	30 June 1975
91. Oman	20 August 1975
92. Kenya	12 September 1975
93. Papua New Guinea	18 May 1976
94. Bahamas	22 July 1976

The Convention has been extended to :

Netherlands Antilles	16 October 1964
Guam, Puerto Rico, Virgin Islands	26 May 1965
Hong Kong	7 December 1965
Bermuda	27 May 1975
Canal Zone, American Samoa Trust Territories of the Pacific Islands	9 September 1975
Midway Islands, Wake Island, Johnston Island	18 March 1976

[No. 11-MTO(26)/76-MA]

R. T. PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1976

का०आ० 4744.—केन्द्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में और संशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उस के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का नाम मद्रास डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1976 है ।

2. मद्रास डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के खण्ड 38 में, उपखण्ड (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) रजिस्ट्रीकृत नियोजक रजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार को, कर्मकार को प्रसामान्यतः और वस्तुतः शोध्य मजदूरी से अधिक नकद या अन्यथा किसी चीज का संदाय नहीं करेगा ।"

[फा० सं० एल डी एम/13/76]

बी० शंकरालिंगम, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 1976

S.O. 4744.—The following draft of a Scheme further to amend the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Madras Dock Workers (Regulation of Empolymqnt) Amendment Scheme, 1976.

2. In clause 38 of the Madras Dock Workers (Regulation of Employment Scheme, 1956, after sub-clause (6), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(7) A registered employer shall not pay a registered dock worker anything in cash or other wise in excess of the wages normally and actually due to the worker."

[File No. LDM/13/76]
V. SANKARALINGAM, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1976

का०आ० 4745.—दिल्ली डेवलपमेन्ट एक्ट 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 52 की उपधारा (1) के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा जनरल मैनेजर, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, दिल्ली विकास प्राधिकरण को लाइसेंस डीड्स, लीज डीड्स तथा करारनामें एवं ऐसे दस्तावेज जिनके सम्बन्ध में सक्षम अधिकरण की अनुमति प्राप्त हो जिनके अनुबन्ध का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक न हो, के अनुबन्ध स्वीकार करने एवं निष्पादन करने के अधिकार भी प्रदान किये जाते हैं।

[सं० एफ 2(1)/75-आई एस बी टी पार्ट-II]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 7th September, 1976

S.O. 4745.—In pursuance of sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby also delegates to the General Manager, Inter-State Bus Terminal of the Delhi Development Authority, its powers to enter into contracts and execute all types of licence deeds, lease deeds, agreements and such other documents in respect of which the sanction of the competent authority is available, where the value of the contract does not exceed Rs. 10 lacs.

[No. F. 2(1)/75-ISBT-Pt. II]

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4746.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं आवास और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन नीचे दी गई अनुसूचि में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया और अब यह भूमि सिंगापुर हाई कमीशन को स्थानान्तरित की जाती है।

अनुसूची

एक्सटेंशन एरिया, डिप्लोमैटिक एनक्लेव, चाणक्यापुरी, नई दिल्ली में स्थित भूखण्ड सं. ई. पी. 6 साईट सं. 7 को अधिसूचना सं. एस. ओ. 1810 दिनांक 20-7-74 के अनुसार एल. डी. ओ. प्लान सं. 2485/1 में दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लगभग 3.073 एकड़ भूमि के भाग को दिखाया गया है।

उपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है :—

उत्तर : प्लाट न. 7
दक्षिण : प्लाट न. 5
पूर्व : सड़क और लान
पश्चिम : पड़ोसी पार्क

[सं. एस. एण्ड एस. 33(3)/74 ए. एस. ओ. (1) 195-97]
ह्रदय नाथ फोतेदार, सचिव

New Delhi, the 7th December, 1976

S.O. 4746.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing & Urban Development, Govt. of India, New Delhi for further transfer to the Singapore High Commission.

SCHEDULE

Piece of land measuring about 3.073 acres situated in the Extn. area of the Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, New Delhi bearing Plot No. E.P. 6/Site No. 7 of Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-74 under section 22 of sub-section (4) of D.D.A. Act, 1957 shown in the Plan L.D.O. No. 2485/1.

The above piece of land is bounded as follows :—

North : Plot No. 7
South : Plot No. 5
East : Road & Lawn.
West : Neighbourhood park.

[No. S&S. 33(3)/74-ASO(I)195-97]
H. N. FOTEDAR, Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1976

का०आ० 4747.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इण्डियन ओवरसीज बैंक, 151, मौन्ट रोड, मद्रास, के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० एन० सिंगारवेलु, बी० ए०, बी० एल० होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या आल इंडिया ओवरसीज बैंक इमप्लाइज यूनियन, मद्रास की० इंडियन ओवरसीज बैंक, 151 माउन्ट रोड, मद्रास के सभी क्षेत्रों में नियोजित सभी सफाई कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारी की बजाए अंश कालिक कर्मचारी मानने और बैंक के प्रबन्धतंत्र तथा आल इंडिया ओवरसीज बैंक इम्प्लाइज यूनियन के बीच हुए तारीख 17-12-1970 के समझौते के पैरा 6(ख) के अनुसार उन्हें सभी लाभ प्रदान करने की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो उक्त कर्मकार किन लाभों के हकदार हैं और किस तारीख से ?

[संख्या एल-12011/34/76-डी०-2-ए]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 30th October, 1976

S.O. 4747.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Indian Overseas Bank, 151, Mount Road, Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. N. Singaravelu, B.A. B.L. shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demand of the All India Overseas Bank Employees' Union, Madras for treatment of all sweepers employed in all areas in Indian Overseas Bank, 151, Mount Road, Madras as part-time employees instead of temporary employees and to grant them all benefits as per paragraph 6(b) of the Settlement dated 17-12-1970 between the management of the Bank and the All India Overseas Bank Employees' Union is justified ? If so, to what benefits are the said workmen entitled and from what date?

[F. No. L-12011/34/76-D.II.A]

New Delhi, the 1st December, 1976

S.O. 4748.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Indian Overseas Bank, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 30-11-76.

BEFORE THIRU T. N. SINGARAVELU, B.A., B.L.,
PRESIDING OFFICER,
INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS
(Constituted by the Central Government)

Industrial Dispute No. 4 of 1976

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Indian Overseas Bank, Madras-2).

BETWEEN

The workman represented by The General Secretary, All India, Overseas Bank Employees' Union, No. 151, Mount Road, Madras, Tamil Nadu,

AND

The General Manager, Indian Overseas Bank, 151, Mount Road, Madras-2.

REFERENCE :

Order No. L-12011/31/75-D.IIA, dated 20-1-1976 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for hearing today, upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal Nandlal Narayanan and Ravi Krishnaswamy, Industrial Relations Officers of the Bank for the Management and the workmen being absent, this Tribunal made the following :

AWARD

This is an Industrial Dispute between the workmen of Indian Overseas Bank, Madras and the Management of the Bank over the Split Duty Allowance payable to the Staff. This dispute was referred to by the Government of India in its order No. L-12011/31/75-D.IIA, dated 20-1-1976 of the Ministry of Labour for adjudication.

2. The issue referred for adjudication is as follows :—

"Whether the action of the management of the Indian Overseas Bank, Madras, in denying the payment of Split Duty Allowance to those staff transferred to Dehra Dun Branch of the said Bank at their own request is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

3. The All India Overseas Bank Employees' Union, Madras has filed a claim statement as follows : Two Clerks employed in the Indian Overseas Bank were transferred to the Dehra Dun Branch of the Bank at their request on 27-12-1974. It was a newly opened Branch and the working hours of the same were decided only after the transfer orders of the two workmen. When these two Clerks claimed Split Duty Allowance in the new Branch, the Management refused to grant them stating that the transfers were on their own request. The action of the Management in refusing to pay the Split Duty Allowance is not tenable and these two Clerks are entitled to Split Duty Allowance of Rs. 7 per mensem.

4. The Management has filed a counter statement as follows : The two employees were transferred to the Dehra Dun Branch at their own request and therefore, as per the Bipartite Settlement dated 14-12-1966, Split Duty Allowance is not payable to the employees who are transferred at their own request to branches where the business hours are split. The said settlement is valid and binding on the parties and therefore these two Clerks cannot claim Split Duty Allowance after having obtained transfers to the place of their choice. The Branch Bank at Dehra Dun was only opened on 27-12-1974, and ever since its inception, it has

been working only split hours. That apart, the reference itself is not maintainable, since the two Clerks wanted transfer to that Branch to suit their own conveniences.

5. The reference was made on 20-1-1976 and it was pending enquiry from January, 1976. The enquiry was adjourned for some reason or other and the matter was posted on 25-10-1976 for enquiry. On that day, the Union wanted an adjournment stating that the date of enquiry was not suitable to them. Therefore, an adjournment was granted on the application by the Union and posted finally for enquiry to 12-11-1976. On the date of enquiry on 12-11-1976, the Management was ready, but the Union has sent a petition for adjournment by post stating that its President is not in Station and therefore the matter may be adjourned. The adjournment was refused and the enquiry went on in the absence of the Union. No employee or the representative for the Union was present in Court even to ask for an adjournment in person.

6. The point for adjudication itself is very simple. The Union claims Split Duty Allowance for the two Clerks transferred to the Dehra Dun Branch, while the Management resists the claim on the ground that the transfer was at their own written request and therefore the Split Duty Allowance of Rs. 7 per mensem is not payable to them as per Clause 8.7 of the Bipartite Settlement Ex. M-8 dated 14-12-1966. Clause 8.7 runs as follows :

> 1. At branches where business hours are split with a minimum break of two hours all full time workmen [excluding (a) watch and ward staff, (b) drivers, (c) sweepers, (d) those who reside in the promises of such branch, and (e) any workman whose hours of work, apart from normal lunch recess, are not split.] :
>
> Provided that no such allowance will be payable to workmen who subsequent to the date of this Settlement are, at their request, transferred to Branches where business hours are split as in item (1) above.

It is common ground that this Settlement Ex. M-8 is in force down to this date. The Management has filed its documents marked as Exts. M-1 to M-8. Ex. M-1 and Ex. M-2 are the applications by the two Clerks of the Bank for transfer to the proposed Branch at Dehra Dun and they are dated 21-1-1974 and 5-12-1974. In these applications, the two Clerks in question made humble requests for transfer to the proposed Branch on personal grounds. The Management granted their request and transferred them to the Dehra Dun Branch, where they joined in December, 1974. They continued to work there down to this date. After securing the transfers, they have now raised a dispute claiming Split Duty Allowance of Rs. 7 per mensem. Paragraph 8 Clause (7) of the Bipartite Settlement of Ex. M-8 between the parties clearly states that Split Duty Allowance is not at all payable to employees who are transferred at their own request to branches where the business hours are split. There is no dispute that the said Branch was working in split hours ever since its inception on 27-12-1974. Therefore, under the terms of Settlement Ex. M-8, the Clerks are not entitled to Split Duty Allowance especially when they wanted a transfer to Dehra Dun to suit their own convenience.

7. However, in the Claim Statement, the Union would put an interpretation of its own stating that the hours of work were split in the Branch only after the transfer of the employees in question. The Union further states that the two Clerks had put in their applications for transfer prior to the opening of the Bank and therefore Paragraph 8.7 will not apply. I have considered this contention carefully and I am satisfied that this interpretation is not at all warranted or tenable.

As stated already, Dehra Dun Branch is working split hours right from the beginning of its commencement on 27-12-1974. Therefore, the plea that the two Clerks had applied for transfer prior to the opening of the Branch is immaterial. Ex. M-1 shows that the Clerks Thiru Ram Singh is a native of Dehra Dun area and he specifically wanted a posting at the new Branch. Similarly, under Ex. M-2, the other transferee very humbly begged the Management on humanitarian grounds to transfer him to the proposed Dehra Dun Branch. Obviously and rightly, these applications for transfer were made by the two applicants before the Staff were formed in the new Branch. The two clerks were quite aware of the opening of the proposed Branch and they wanted posting to that Station for their own benefit, since they are residents of that area. Ex. M-4 dated the 24-12-1974 is the order of transfer intimating Thiru Ram Singh that he should report for duty immediately at Dehra Dun Branch. Ex. M-3 is another communication dated 11-12-1974 mentioning the salary and allowances to be paid to them and stating that the transferees will not be entitled to any travelling allowances, since the transfers were at their own request. Ex. M-3 directs the transferee to join the proposed Dehra Dun Branch on 16-12-1974. In these circumstances, no Split Duty Allowance can be paid to the two employees who sought a transfer at their own request. When a member of staff is transferred at his own request, it is common knowledge that he ordinarily loses the benefits of travelling allowance, seniority for the purpose of special allowances, etc. These two Clerks were fully aware that they will lose these benefits if they were transferred to a place of their own choice and still they bargained for it and got it. It is not now open to them to turn round and contend that the working hours of the Branch were split only after their request for transfer to that Station. To say the least, this does not come in good grace, especially when the Split Duty Allowance is a very small sum of Rs. 7 per mensem. Further, the Branch at Dehra Dun itself was opened only on 27-12-1974 and the two Clerks joined there even at the commencement irrespective of the fringe benefits that they were perhaps drawing in the previous Stations. I am therefore satisfied that the claim of Split Duty Allowance in the face of paragraph 8.7 of Ex. M-8 is frivolous. It follows that the Management was justified in denying the payment of Split Duty Allowance to these two transferees who wanted to be posted at Dehra Dun Branch. In this connection, it is submitted by the Management that the two transferees are quite happy at Dehra Dun having joined the Branch in December, 1974 and that, they are not interested in this dispute. This plea is quite plausible and it would appear that the Union is supporting an unworthy cause. For all these reasons, I hold that the action of the Management is justified and the two employees will not be entitled to any relief. An award is passed in these terms. No costs.

Dated, this 12th day of November, 1976.

T. N. SINGARAVELU, Presiding Officer

WITNESSES EXAMINED

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

For workmen : Nill.

For Management :

Ex. M-1/21-1-74—Application of Thiru Ram Singh Rawat to the Bank for transfer.

Ex. M-2/5-12-74—Application of Thiru Keshar Singh Bisht to the Bank for transfer.

Ex. M-3/11-12-74—Letter from Indian Overseas Bank, New Delhi to the Manager, Indian Overseas Bank, Alwar transferring Thiru Keshar Singh Bisht to Dehradun Branch.

Ex. M-4/24-12-74—Reliveing order issued to Thiru Ram Singh.

Ex. M-5/10-8-75—Letter from the Union to the Regional Labour Commissioner (C) Madras regarding Split Duty Allowance.

Ex. M-6/11-10-75—Reply letter from the Bank to the Assistant Labour Commissioner (C)-II, Madras regarding Split Duty Allowance.

Ex. M-7/22-10-75—Conciliation failure report.

Ex. M-8/14-12-66—Settlement between parties.

Note : Parties are directed to take return of their document/s within six months from the date of the Award.

[F. No. L-12011/31/75-DII.A.]

T. N. SINGARAVELU, Industrial Tribunal.

S.O. 4749.—In pursuance of section 17 of the Industrtial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Central Bank of India, New Delhi and their workmen,

which was received by the Central Government on the 29-11-76.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

C.G.I.D. No. 40 of 1975

BETWEEN

The management of Central Bank of India through their Zonal Manager Parliament Street, New Delhi,

AND

Their workmen as represented by the Central Bank Employees' Union, Central Bank Building, Chandni Chowk, Delhi.

PRESENT :

Shri Tara Chand—for the workmen.

Shri S. P. Bhaskar—for the management.

AWARD

The Central Govt. on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L-12012/62/75/DII/A dated the 15th July, 1975 with the following terms of reference :—

"Whether the management of the Central Bank of India Delhi, is justified in not designating Shri Ashok Kumar Jain as Accounts Clerk? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. When the case came up today for hearing before me, a memorandum of settlement was jointly filed by Shri Tara Chand on behalf of the workmen and by Shri S. P. Bhaskar on behalf of the management. Both the above-named representatives of the parties verify and admit the terms of settlement and prayed that a no dispute award might be passed in this case. In view of this, I have no alternative but to pass a no dispute award which is passed accordingly.

10th November, 1976. D. D. GUPTA, Presiding Officer

[F. No. L-12012/62/75-D.II.A.]

S.O. 4750.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the National and Grindlays Bank Limited, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th November, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,

CALCUTTA

Reference No. 38 of 1975

PARTIES : Employers in relation to the management of National and Grindlays Bank Limited,

AND

Their Workmen.

REFERENCE :

On behalf of Employers—Sri M. S. Bala, with Sri K. C. Roy.

On behalf of Workmen—Sri D. L. Sen Gupta, Senior Advocate, with Sri H. L. Roy, Advocate.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking

AWARD

By Order No. L. 12011/25/74/LRIII dated 10th February, 1975, the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of National and Grindlays Bank Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference reads :

"I. Whether the Workmen, (Caretaker, Electrician, Durwan and Sweeper) working at 17, Alipore Road, Calcutta-27 for looking after the property of National and Grindlays Bank Limited are entitled to the following facilities from that Bank ? If so, to what extent and from what date ?

(1) Annual Leave, privilege leave and medical leave. (2) Medical expenses, (3) Uniforms, (4) Retirement Benefits, and (5) Holidays.

II. What should be the working hours of the workmen concerned.

III. Whether the workmen concerned are entitled to bonus for the year 1973 ? If so, at what rate ?

IV. Whether the workmen should be placed in a suitable grade ? If so, what should be the details of the Grade ?"

2. The concerned workmen who claim benefits under the Reference at the time of the trial are found to be five in number. Their names, designation, date of appointment and salaries are described in Annexure 'A' to the written statement of the Union which espoused their cause and it reads as follows :—

Sl. No.	Name of the Employee	Designation.	Date of Appointment	Initial Salary	Present Pay
1.	Sri Bimal Naskar	Electrician	4-11-69	145/-	168/-
2.	Sri Amar Bahadur	Durwan	1-2-67	120/-	134/-
3.	Sri Katak Bahadur	do.	4-3-71	120/-	127/-
4.	Sri Ganesh Bahadur	do.	6-8-71	120/-	127/-
5.	Sri Mahadeo Sing	Sweeper	7-1-71	80/-	80/-

3. The Commercial and Factory Establishment Staff Union which filed the written statement on behalf of the workmen raised the contention that these workmen have been in the employment of National & Grindlays Bank Limited eversince they joined service and that salaries had been disbursed by them, though the Bank had set up one Talbot & Company, Calcutta as a middleman and agent to work purely at the discretion and desire of the bank to manage the work of these employees. The union has, therefore, stated that these workmen are entitled to get the salary and other benefits as the regular employees of the Bank and as such they shall be provided with the same salary scales and other emoluments as described in Annexure 'C' to their written statement. It is alleged that in spite of the demands made by the Union the bank did not comply with their request. A conciliation was sought to be effected in the presence of Assistant Labour Commissioner (C), Calcutta but it ended in failure and hence the present reference by the Government of India to this tribunal for adjudication.

4. The National & Grindlays Bank Limited in their written statement contended that the Commercial and Factory Establishment Staff Union is an outside union, not connected in any manner with the bank or its workmen in as much as the Union has certainly not as its members either a majority or an appreciable number of workmen supporting the cause of the concerned workmen. According to them, the said union has no representative character to espouse the cause of the workmen as alleged. On the contrary, the National & Grindlays Bank Employees' Union is a recognised union of the employees of the bank and as such they alone have the representative character to espouse the grievances of these workmen if any. At any rate, it was contended that in view of the espousal of the cause of the workmen by a minority union no industrial dispute is in existence as required by law and as such the reference has to be rejected as invalid and illegal. They also stated that the workmen concerned in the dispute have never been their workmen. On the contrary, they stated that they have been employed by Talbot & Company who in their turn were engaged by the National & Grindlays Bank Limited, I.C.I. (India) Private Limited and the First National City Bank who are the three proprietors of the property in question. On the terms and conditions of the agreement, the Talbot & Company was to appoint the necessary workmen to look after and maintain the property at 17 Alipore Road, Calcutta-27 which is otherwise known as "The White House". It is also stated that the workmen employed for the upkeep and maintenance of the residential property are not workmen as required by Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947 and as such it is stated that these workmen are not employed in an industry. In the result, they contend that the workmen cannot get any relief from National and Grindlays Bank Limited in respect of their salary or other benefits. They have also indicated in the written statement the property in question belongs to three different owners including the National & Grindlays Bank Limited and two other owners are said to be I.C.I. (India) Private Limited and the First National City Bank who have not been made parties to the reference.

5. On account of the contentions raised in the respective written statements the following points have arisen for determination :

(i) Whether the employees concerned in the reference are the workmen of the National & Grindlays Bank Limited as defined in Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947 ?

(ii) Whether the espousal of the cause of the workmen by the Commercial & Factory Establishment Staff Union, Calcutta has to be construed an industrial dispute as between the management and the workmen concerned in the Reference ?

Point (i) :

6. The disputed property is at 17, Alipore Road, Calcutta-27 which is otherwise known as the 'White House'. It is more or less established at the trial that there are now five buildings in this property. Of these buildings two buildings are in the possession and occupation of National & Grindlays Bank Limited and two buildings are in the possession and occupation of I.C.I. (India) Private Limited and one is in the possession and occupation of the First National City Bank. These five buildings were built in five plots of land which originally belonged to National & Grindlays Bank Limited. In respect of this land there was an agreement between the three proprietors. That agreement is marked as Ext. M-6 (a) dated 4th November, 1965. Under the agreement the entire plot of land was divided into six plots i.e. A, B, C, D, E and F. Plot F was kept in common between the three proprietors. Plots A & B were retained by National & Grindlays Bank Limited. Plots C & E were sold away to I.C.I. (India) Private Limited and Plot D to First National City Bank. Each of these proprietors was also entitled under the document an undivided share over the plot F which constituted the Garden Road way and other appurtenants in the premises of the buildings. Later, I.C.I. (India) Private Limited sold away Plot E to one of its Associate Companies known as Indian Explosives Limited under Ex. M-11 dated 3rd April, 1973. The sale was effected as the National & Grindlays Bank Ltd. did not assert their right of pre-emption which was conferred upon it under the terms of the agreement, Ext. M-6 (a) to purchase any of the plots included therein. Any way, these buildings are separately occupied by these three proprietors. But, with regard to the management and upkeep of the property as well as the premises of the buildings the three proprietors entered into the agreement Ext. M-6(a) under which the National & Grindlays Bank Limited was constituted as the Agent and they have been invested with certain rights and powers which are indicated in paragraph 8 of Ext. M-6 (a). Sub-clauses (f), (g) & (h) of paragraph 8 and paragraph 9 are relevant in this case. The said sub-clauses and paragraph 9 read as :

"8(f) In connection with the maintenance upkeep and repairs of and to the said items, and replacement of defective or worn out materials appertaining thereto the Vendor or its authorised agent or agents shall be at liberty to engage and dismiss such staff and purchase such equipment as in the opinion of the Vendor may be requisite or necessary and to pay the wages or remuneration of such staff as and when they fall due for payment and to take all such other steps and incur such other expenditure as may from time to time appear to the Vendor to be expedient or necessary.

(g) Twice in every calendar year or oftener if thought fit the Vendor shall submit to the First Purchaser and to the Second Purchaser respectively a statement of account showing in sufficient detail the amount of expenditure under different heads incurred by the Vendor pursuant to sub-clause (f) hereof during the previous six months or shorter period, as the case may be, and the First Purchaser and the Second Purchaser will each of them forthwith pay to the Vendor the expenditure as shown by the said statement of account according to the said proportionate shares.

(h) In the event of the Vendor ceasing to be the owner of Plot Nos. A and B shown on the said plan the responsibilities referred to in sub-clauses (d), (e), (f) and (g) hereof shall devolve upon the First Purchaser if it is still the owner of Plots C and E shown on the said plan and failing the First Purchaser upon the Second Purchaser provided that if neither the First purchaser nor the Second Purchaser are the owners of any of the land comprised in the said Plan at the time when the Vendor ceases to be the owner of plots A & B the aforesaid responsibilities shall devolve by agreement between the Vendor and the Purchaser from the Vendor upon such Purchaser.

9. It is lastly agreed by and between the parties hereto that the provision of these presents shall pass with the said Plots A, B, C, D, E and F."

7. On a reading of the above conditions and limitations it is clear that National & Grindlays Bank Limited was constituted as Agent of the other proprietors with regard to the management and upkeep of the buildings and premises in the White House. They had the right to engage and dismiss such staff and purchase such equipment as in the opinion of the Vendor (National & Grindlays Bank) may be required or necessary and pay wages of such staff as and when they fall due for payment and to take all such other steps and incur such other expenditure as may from time to time appear to the Vendor to be expedient or necessary. The other two proprietors have to reimburse the Grindlays Bank Limited their share of liabilities. That was being done in this case from the beginning after Ext. M-6 (a) came into existence. The note, Ext. M-2, contains the mutual discussions among the proprietors of the buildings for determination of the share of expenses for the upkeep and maintenance of the White House. It will also be necessary to point out that after the agreement came into force each of these proprietors had paid their share separately though initial payment was being made by the Grindlays Bank. Ext. M-8 is the copy of the amount covered by a cheque which the First National City Bank sent to the Grindlays Bank Limited towards their share of contribution. Ext. M-9 is another copy of the amount of the cheque towards the proportionate share of the expenditure due from the First National City Bank. Ext. M-10 is a similar account of the amount sent by cheque by the same bank to the Grindlays Bank for the year ending 31st December, 1975. The covering letters by the Grindlays Bank are also attached with Ext. M-8, M-9 and M-10 calling upon the other proprietors to pay their share of amount. The share of the First National City Bank, Indian Explosives Limited and I.C.I. (India) Private Limited was 1/5th each and that of Grindlays Bank Limited was 2/5th of the entire amount of the expenditure to be incurred in respect of items which include the salary of the staff, Corporation tax of the buildings, etc. So, the Grindlays Bank have to maintain accounts in respect of the upkeep of these buildings and after disbursement, they have to collect the proportionate share of the amount due from other proprietors. The fact that the Grindlays Bank Limited has constituted into the position of an Agent for and on behalf of other proprietors was evident not only from this document but also from evidence of two witnesses examined on management's side as MW-1 and MW-2. MW-1 is the Credit and Marketing Manager of the Grindlays Bank, Calcutta. He is the resident in one of the five houses in the White House. MW-2 was the Manager of the First National City Bank, Calcutta. He is also a resident in one of the houses in the White House. They admit that the Grindlays Bank had been collecting the proportionate share of the maintenance amount from the other two proprietors though the Grindlays Bank made the initial payment towards maintenance in this regard. So, it can be said in the circumstances of the case that Grindlays Bank was an Agent of the proprietors of the White House and as such Grindlays Bank was competent to employ, dismiss and deal with the workmen who are employees of the White House with regard to the maintenance and upkeep of the premises. The fact that there are two other proprietors who are entitled to three houses in the White House would not in any manner affect the right of the Grindlays Bank to manage the property as an Agent of all the three proprietors. I find therefore that the Grindlays Bank Limited has to be declared as the employer so far as the dispute in question is concerned.

8. The next contention on the same point is whether the five employees are the workmen of the Grindlays Bank Limited as required by Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. In this regard there was the oral evidence of MWs 1 and 2 and that of WW-1 who is the President of the Commercial and Factory Establishment Staff Union. The management in this case has put forward a contention that the workmen concerned in this case are employees of one Talbot & Co. and not that of the Grindlays Bank Limited. None on behalf of Talbot & Company has come forward to give evidence in this case to support the contention that the emp-

loyees in question had been appointed at their instance. There was absolutely no written order of appointment issued in the case either by Talbot & Company or by Grindlays Bank Limited. So, we have to examine the evidence and other circumstances of the case to ascertain whether the workmen are the employees of the Grindlays Bank Limited or they are workmen of Talbot & Company. In this regard it is necessary to refer to a letter, Ext. M-5 the original of which is Ext. M-5(a) dated 28-4-65. This letter was said to have been sent by Talbot and Company to Grindlays Bank Limited. The Management has relied upon this letter to show that the employees in quesion had been engaged by Talbot & Co. The first part of Ext. M-5 (a) is to be effect—

"That we engage—

(i) An overall Supervisor ;

(ii) A semi-skilled 'mistri' to look after the filtration plant;

(iii) Durwans for manning the main gate to the estate."

The second part of the letter is to the effect that Talbot & Company would carry out the work on behalf of the management on the following terms and conditions :

"(a) That our fee will be Rs. 300.00 per mensem, that is Rs. 60.00 per property ;

(b) That all outgoings and including staff salaries as above will be debited to your Account."

In page 2 of the letter there is also a sentence, "....we suggest that four durwans are employed". But none of the averment contained in Ext. M-5(a) would indicated that Talbot & Co. had any independent right to appoint the workmen to the White House. Their right to management was to be paid for the extent of Rs. 300/- per mensem and all other expenses including staff salaries were to be made by the Grindlays Bank Limited. So, the position is clear from Ext. M-5(a) itself that Talbot & Co. was not to pay the salaries of the workmen as if the workmen were their employees. They are only to get Rs. 300/- per mensem towards the charge of their supervision and nothing more. If an emolument of a consolidated sum was agreed to be paid to Talbot & Co. towards the upkeep and maintenance of the White House with liber to appoint and dismiss the workmen, then it could have been contended that Talbot & Co. was an independent contractor and not an agent or servant of the Grindlays Bank Limited. It is clear from some other documents in the case to show that Talbot & Co. did not take upon themselves the right which vested in the owners under the agreement. In Ext. M-1 which is the same as Ext. W-3 dated 15th March, 1974, Talbot & Co. asked the direction of the National & Grindlays Bank Limited for sanction of increment to the disputed workmen. Talbot & Co. has informed Katak Bahadur, one of the durwans, vide Ext. W-2 dated 9-8-73, that an icrement had been given to him with effect from 1st August, 1973 as instructed by National & Grindlays Bank Ltd. Exts. C-1, C-2 and C-3 will not in any manner affect the position of Talbot & Co. which issued the certificates Exts. C-1 and C-2. Those certificates were issued for identification of the workmen concerned and they could not serve any other purpose. It has been explained by MW-2 that Talbot & Co. was obliged to take instructions from National & Grindlays Bank as and when increments were ordered because of the fact that any additional financial burden could be incurred only with the consent of the owners of the buildings. If that was the idea behind the communication like Ext. M-1, the wording of the communication would have been different. Talbot & Co. would have stated that they had ordered increments to the employees and that fact may kindly be taken into account for making future payment. That was not the contents of those communications. As a matter of fact, Talbot & Co. wanted instructions from the National & Grindlays Bank for sanctioning increment to be given. It was not issued as a piece of information to be communicated to the Grindlays Bank Limited because of the additional burden to be cast on them for payment. The position of Talbot & Co., as is evident from the circumstances of the case was that of a servant or agent of Grindlays Bank Limited. In the matter of supervision of the work of the staff employed at the White House, Talbot & Co. never asserted their right that they are the employers of those workmen. On the contrary, appointment of Talbot & Co. as an agent of Grindlays Bank was consistent with the agreement contained in clause (f) of paragraph 8 of Ext. M-6(a) amongst the proprietors of the White house. On the basis of that clause the Grindlays Bank was authorised in their own right or through their agent to engage and dismiss such staff who was to be employed in the White House. It cannot be said that the right of disciplinary action or even dismissal order can be passed by the Talbot & Co. against the workmen concerned when there is a strict stipulation in clause (f) referred to above that the Grindlays Bank was empowered through themselves or through their agent to engage and dismiss the staff and pay wages or remuneration of such staff as and when they fell due for payment. There was nothing on record to establish that the Grindlays Bank had delegated their right of appointment and dismissal of the employees to Talbot and Company.

9. In this regard I may refer to a decision reported in Shivanandan Sharma and Punjab National Bank Ltd., 1955 I LLJ, 688. In that case a body of persons known as treasurers were appointed by the bank and the treasurers were to appoint cashiers and other assistants. In that case the appointment has to be approved by the bank and the treasurers would not continue to employ those workmen in whose fidelity and efficiency the bank had no confidence. The Supreme Court held in that case that if a master employs a servant and authorizes him to employ a number of persons to do a particular job and to guarantee their fidelity and efficiency for a cash consideration, the employees thus appointed by the servant would be, equally with the employer, servants of the master. In a similar case though on different facts the Supreme Court held in D. C. Dewan Mohideen Sahib & Sons and another v. United Bidi Workers' Union, Salem, and another, 1964 II LLJ, 633 that the Bidi workers working in the premises of the contractors were the workmen of the employer and not of the contractor. In that case the manufacturers supplied bidi leaves to the workers and they rolled bidis in the premises of the contractor who was appointed to look after the rolling work on remuneration. The question was whether they were independent contractor or agent of the employer. On a review of the case law on the point the Supreme Court held that the bidi rollers were the workmen of the manufacturers and that the contractors were not independent contractors. On the analogy of the above case it can be said that the facts of the instant case also fall in line with those cases. It cannot be said from the facts and circumstances of this case that Talbot & Co. was an independent contractor. No party to the agreement Ext. M-6(a) had taken upon it that they should appoint independent contractor for the maintenance and upkeep of the White House. On the contrary, they had only authorised Grindlays Bank Limited to employ and dismiss the staff of the White house and they had also been authorised to get the work done through an agent or a servant. In the context of that provision and the other evidence adduced in the case I am constrained to hold that the workmen in this case are the employees of the Grindlays Bank Limited.

10. Another question which cropped up in the course of the trial was as to whether the workmen concerned could be regarded as doing the work in an industry. The definition of an 'industry' is wide enough to include workmen employed in any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen and it would not be correct to state that simply because a workman happens to be employed as a watchman or durwan or an electrician or even a sweeper they could not fall within the definition of the term "employees". In this regard reference may be made to a decision reported in J. K. Cotton Spinning and Weaving Mills Company, Ltd. and Labour Appellate Tribunal of India and others, 1963 II LLJ, 436, where it is stated,

> "In this connection, it is hardly necessary to emphasise that in the modern world industrial operations have become complex and complicated and for the efficient and successful functioning of any industry, several incidental operations are called in aid and it is the totality of all these operations that ultimately constitutes the industry as a whole. Whenever it is shown that the industry has employed an employee to assist one or the other operation **incidental** to the main industrial operation, it would be unreasonable to deny such an employee the status of a workman on the ground that his work is not directly concerned with the main work or operation of the industry."

11. It is found that the workmen in this case had been employed and paid by the Grindlays Bank; that they work subject to control and supervision of their agent ; the condition of their service, the payment of salary and the increments to be paid to the workmen were subject to the control of

the bank; the houses in question had been allotted to the officers of the respective institutions as a condition of their service. It would follow from these circumstances that the workmen in question are the employees of the bank which conducts industrial enterprise. The above decision has been followed in a later decision reported in Ramtahel Ramanand and others v. Ahmedabad Manufacturing and Calico Printing Company, Ltd., 1968 II LLJ, 46. Taking these two decisions into consideration I am of the opinion that these workmen had been employed in an occupation which is incidental to the main industrial undertaking by the Grindlays Bank Limited and as such they are workmen as defined in Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. Accordingly, my finding on this point is in favour of the Union which espoused the cause of the five workmen in question.

Point No. (ii) :

12. There is the evidence of the President of Commercial and Factory Establishment Staff Union as WW-1. He has produced a register where the names of these five workmen are entered as members of the union. Copy of that register is marked as Ext. W-5. It had been compared to the original which was taken back later on. These workmen had paid subscription to the union long before the reference in question as members of the union and they continue to be members. On 30-8-1974 the Executive Committee meeting of the union was held at the office of the union when these workmen and others were present. Ext. W-6 is the Minutes Book maintained by the Union. WW-1 proved that the workmen were present at the meeting and they decided that the cause of the workmen shall be espoused by the union and that it should be taken up to the authorities for appropriate relief. Accordingly, the union made a demand on the Grindlays Bank Limited through a notice copy of which is marked as Ext. W-4 dated 30-8-74. There was a conciliation at the instance of the Assistant Labour Commissioner but that conciliation failed and hence the reference was made. The 17-Alipore Road, Calcutta-27 which is known as the 'White House' is a separate establishment of the Bank. If that is a separate establishment, the employees of that establishment have the right to organise and become members of a union. It is necessary in this connection to point out that the Bank has disputed the representative capacity of the union as well as the membership of the employees to that union. According to them, the five members of the union by themselves could not create an industrial dispute when a large body of their workmen did not support them. According to the evidence in the case there are 1750 employees in the Grindlays Bank in the area concerned and that none of those employees had given any support to the demand made by the five workmen in the case. So, according to the management, no industrial dispute has come into existence and as such the reference made is inoperative and illegal.

13. The question of representative character of the union to espouse the cause of the workmen so as to constitute an industrial dispute has been the subject matter of many decisions. All these decisions have been considered at length in the latest decision of the Supreme Court reported in Workmen of Indian Express Newspaper Private Limited and the Management of Indian Express Private Ltd., 1970 LL LLJ. 132. The principles of an decision reported in Workmen of Dharampal Premchand v. Dharampal Premchand (Saughandi), 1965 I LLJ. 668 were examined by the Supreme Court and the following conclusions had been arrived at :

> "....held that notwithstanding the width of the words used in S. 2(k) of the Act a dispute raised by an individual workman cannot become an industrial dispute unless it is supported either by his union or in the absence of a union by a number of workmen, that a union may validly raise a dispute though it may be a minority union of the workmen employed in an establishment, that if there was no union of workmen in an establishment a group of employees can raise the dispute which becomes an industrial dispute even though it is a dispute relating to an individual workman, and lastly, that where the workmen of an establishment had no union of their own and some or all of them have joined a union of another establishment belonging to the same industry, if such a union takes up the cause of the workmen working in an establishment which has union of its own, the dispute would become an industrial dispute if such a union can claim a representative character in a way that its support would make the dispute an industrial dispute."

14. Basing the argument on the last clause of the above decision the learned Counsel of the management pointed out that no union working in any other industry can espouse the cause of the workmen of the bank unless a majority or a substantial number of workmen of the bank are members of that union. It is pointed out that out of 1750 employees none have come forward to support the cause of the workmen concerned and as such the union which espoused the case of the workman has no representative character in a way that its support would make the dispute an industrial dispute, I think this argument is not acceptable in view of the fact that the workmen concerned belongs to a separate establishment and the workmen of that establishment organised themselves separately with a separate union. It is relevant in this regard to point out a decision of the Madras High Court reported in Buckingham and Carnatic Company Ltd., and Its Staff Union and another, 1959 II LLJ, 781. The relevant portion that posed for consideration in that case is at page 782 and it reads :

> "...If in an industrial establishment which employs several workmen who fall into more or less well-defined sections having regard to the nature of the work in which they are employed, a dispute is raised by a few of the workmen in one of such sections and that dispute is taken up by a substantial number of persons employed in that section, whether organized as a union or not can it be said that there is an industrial dispute within the meaning of that term as defined in the Industrial Disputes Act, or is it only when a majority or a substantial number of workmen employed in all the sections of the establishment take up that dispute or espouse their cause that an industrial dispute can be said to arise. The question is likely to arise in large establishments like the appellants in which thousands of workmen are employed. So far as we are aware, there is no provision of law which prohibits the existence of more than one union or association of employees in a particular industrial establishment. here is nothing to prohibit such section of the establishment having a union the membership of which is confined to the employees in that section Even if all the employees in an establishment are employed in the same kind of work, there may be two different unions with separate membership. There may also be several industrial establishments the employees in which are not members of any union at all. In this country as yet there is no organized system of recognized collective bargaining units in respect of each industrial establishment or sections there."

At page 744 of the same decision the argument of the Counsel who opposed the union's case was answered by a detailed reasoning that in a particular establishment of an industry having separate grievances and conditions could organise themselves into a separate union and make a demand irrespective that there are large number of workmen in the industry. In that particular case there were about 10,000 workmen as members of the Madras Labour Union. Of those workmen about 700 employees were in the clerical section. Out of the 700 employees 434 employees were members of the Buckingham and Carnatic Mills Staff Union. It was that union which espoused the cause of 47 of such members. The question was whether the dispute raised by those 47 employees which had been espoused by the Buckingham & Carnatic Mills Staff Union which has a membership of 434 out of 700 of the clerical staff was an industrial dispute. That was answered in favour of the union that they could raise an industrial dispute. In this case all the five employees of the establishment have raised an industrial dispute through Commercial and Factory Establishment Staff Union. That it was an outside union or that it was a minority union is no consideration. It is established that a mere industrial dispute would not fall within the scope of the definition of that what is contemplated as collective dispute. The test in respect of collective dispute is whether on the date of reference the dispute was taken up as supported by the union of the workmen of the employer against whom the dispute is raised by an individual workman or by an appreciable number of workmen. That is what was decided in Bombay Union of Jounalists and others v. The "Hindu", Bombay and another, 1961 II LLJ, 436. It is clear on the basis of the above decisions that a dispute in this case ha dbeen raised by the Commercial and Factories Establishment Staff Union in respect of all the workmen of

the establishment which is one of the establishments under the Bank and as such there has been an industrial dispute as against an individual dispute.

15. The last clause of the reasoning set out at page 137 of the decision in 1972 II LLJ, 132, does not in any manner indicate that an outside union cannot take up a dispute so as to convert it into an industrial dispute if the establishment is in the same industry. The establishment as in the White House is in the same industry and as such the union took up the cause of the workmen working in that establishment which has no union of its own except the union in question. I find therefore that there has been a valid espousal of the cause of the workmen by the concerned union as an industrial dispute. This point is also found in favour of the workmen.

16. In view of the above two findings, the workmen are entitled to the relief asked for in Annexure 'C' attached to the written statement of the union. It has been proved by WW-1 and no question had been asked against the correctness of his evidence as to the claims he set up in favour of the workmen on the basis of Annexure 'C', the relevant portion of which is set out below :

Grade Scale and D.A.

Durwan and Sweeper	..	Rs. 119 to Rs. 200 in 20 years span plus Rs. 228/- D.A. plus Rs. 18 House rent plus Rs. 18 Compensatory Allowance.
Electrician	..	Rs. 119 to Rs. 200 in 20 years span plus Rs. 35/- Special Allowance with usual D.A.
Provident Fund	..	8⅓% own and 8⅓% Employers
Annual Leave	..	30 days in a year.
Medical Leave		15 days yearly with full pay.
Medical Expenses	..	Rs. 145 per annum.
Uniform	.	2 sets of cotton clothes, one set woollen every third year.
Retirement benefits	..	Pension or gratuity if not 30 years service completed.
Holidays	.	P/L 30 days, C/L 12 days, Medical 15 days (six months on prolonged illness) plus all Gazetted holidays.
Working hours	..	6.30 hours on week days from Monday to Friday and 4.30 hours on Saturday.
Leave fare concession	..	Once in every three years upto 1500 kilometers or to native place.

So, the workmen would be entitled to the benefits as shown above.

17. In the result, an award is passed in terms of paragraph 16 above. The workmen will not be entitled to any bonus for the year 1973 as claimed in Annexure 'C' to the written statement of the Union. The claims as allowed above will take effect from 1st November, 1976.

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

Dated, Calcutta, the 19th November, 1976.

[F. No. L-12011/25/74-LR-III/D.II.(A)]

R. P. NARULA, Under Secy.

New Delhi, the 3rd December, 1976

S.O. 4751.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Central Public Works Department, New Delhi and their workman, which was received by the Central Government on the 29th November, 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

C.G.I.D. No. 41 of 1975

BETWEEN

Central Public Works Deptt., through Executive Engineer (Construction), Division No. VI, 45-C, Irwin Road, New Delhi.

AND

Its workman Shri Shyam Lal, Qr. No. 9, Block No. 1, D.D.A. Quarters, Garhi, Lajpat Nagar, New Delhi.

APPEARANCE :

Shri D. S. Adel—for the management.

Shri R. K. Bashkar—for the workman.

AWARD

The Central Government on consideration of a report submitted by the Conciliation Officer that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L-42012(3)/74-LR. III/D. 2(B) dated the 26th July, 1975 with the following terms of reference :—

"Whether the termination of services of Shri Sham Lal, ex-employee of the Construction Division No. VI, Central Public Works Department, New Delhi, with effect from 15-3-74 is justified ? If not, to what relief is he entitled ?

2. The applicant averred that he was employed as Chowkidar by the Executive Engineer (Construction) Division No. 6 in the year 1972, but his name was put on the muster roll for six months. On 15-3-74, his services were terminated without any notice and without paying him wages due to him for making representations for confirmation as his juniors had been made quasi-permanent. It was pleaded that the action of the management was illegal and unjustified; hence the prayer that he be re-instated with full back wages and continuity of service.

3. The respondent stated that the workman was employed as Beldar on muster roll purely on temporary basis. It was pleaded that the question of terminating the services of the workman did not arise as the workman was employed as casual labour on Muster Roll and that he was not engaged on Muster Roll after 13-3-74 as his services were not required. It was, therefore, prayed that the claim of the petitioner be dismissed.

4. On these pleadings the following issue was framed :—

ISSUE :

1. As in the term of reference.

5. In oral evidence the management examined Shri R. K. Sachdev—MW1. In rebuttal came Shri Shyam Lal—the workman concerned-WW1 and Shri N. K. Narank-WW2.

6. Arguments were, then, heard.

ISSUE No. 1

7. The first contention of the management is that the workman was employed purely on temporary basis as beldar, that is, casual labour, on muster roll. His services were, then, not required after 13-3-74 ; therefore, they came to an end.

8. The case of the applicant, however, is that he worked as a Chowkidar and office peon though his name was put on the muster roll. His services could not, therefore, be terminated without a notice and without paying him compensation.

9. The intention of the management in pleading that the workman was employed, as a beldar on muster roll, on purely temporary basis was that the work for which he was employed finished and alongwith it the services of the workman, also, came to an end as they were no longer required. Thus, the first question for determination is whether the workman worked as a beldar at a construction site or he worked as a chowkidar and office peon.

10. Giving his evidence in support of his case, the workman Shri Shyam Lal said in his statement WW2, "I worked for the C.P.W.D. since September, 1972. I worked as a chowkidar in the "Bada" where houses stood constructed and vacant.

I worked as chowkidar there for two months and a half from the date, I joined. There was no other chowkidar, there. I was, then, sent to C.P.W.D. inquiry office at C-45 Irwin Road where I issued things like cement, ballies, iron etc. from the store. I worked there for two years minus 2-1/2 months." He further said, "I never took leave and worked continuously as chowkidar on Sundays during the day". This evidence was corroborated by Shri N. K. Narank-WW2 a junior engineer of the management, itself. He said, "It was I who employed the applicant Shamlal. He was posted first at the Lady Reading School Bara Hindu Rao to guard the quarters which lay vacant, there. He remained there for 2-3 months. He was, then, sent to Irwin Road. There he worked as a general cleaner and office peon when the office peon went on duty. He did not work as a chowkidar there."

11. In its evidence the management produced Shri R. K. Sachdev MW1 who said, "The applicant worked for the management as beldar on muster roll from time to time purely as a temporary hand. I came to this Division in 1975 and the claim is for a period prior to my coming to this Division. I say only as per record that he was a beldar. What did he work as? I do not know". He further said, "I have no personal knowledge of any kind about the applicant. We keep no beldar for office work."

12. Considering this evidence, I am of the opinion that the statement of Shri Sachdev MW1 does not rebut the evidence on the workman's side. Shri Sachdev admitted in so many words that firstly he did not have any personal knowledge of any kind about the workman and secondly he did not know as to what did the workman work as. All that he said was that the workman, was employed as a beldar and shown in the muster roll. Now, so far as this was concerned it was admitted by the workman himself that he was shown on the muster roll. His case was that he worked as a chowkidar and not a beldar and showing him on the muster roll was only for the purposes of payment of his wages. He succeeded in proving that he worked as a Chowkidar and an office peon, though, he was shown on the muster roll as beldar which was only for the purposes of drawing his wages. It is, therefore, held that the workman worked as a chowkidar first and then as office peon and not as a beldar. The management, thus, failed to prove that the workman was employed on a construction site, as a beldar.

13. It, also, failed to prove that the work on the muster roll of which the applicant was employed as a beldar finished. Shri Sachdev MW1 simply said, "Last day worked by the applicant was 13-3-74 as per the record. There is no record of his further employment." Shri N. L. Narang WW2, also, was not asked in cross-examination that the work on which the workman herein was employed came to an end; therefore, the question of not requiring the services of the workman did not arise and there was no justification for the termination of his services.

14. Evidently, the workman herein became a 'workman' under the Industrial Disputes Act, 1947 having worked as a chowkidar and an office peon. It was, also, admitted by the management that he had been in continuous service for not less than one year, having worked for more than 240 days from 18-10-72 to 3-10-73 and for one hundred and twenty days from 8-10-73 to 13-3-74 (Vide Section 25-B of the I.D. Act, 1947). He was, therefore, entitled to one month's notice or wages in lieu of such notice, as also, compensation equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months. The management did not do either of these two things. The termination was, therefore, illegal, too, as laid down in Section 25-F of the I.D. Act.

15. The management tried to say that the notice had been dispensed with by the workman himself by means of Ex. M 3 dated 15-1-74, in which it had been stipulated that the appointment could be terminated at any time without any notice. This contention is without force as this stipulation was clearly against the statute and none could contract out of one. The stipulation was, therefore, illegal and without force and void.

16. The issue is, accordingly, decided in favour of the workman.

17. The result is that the termination of services of the workman, herein, with effect from 15-3-74 is unjustified and illegal. He is, therefore, entitled to re-instatement with full back wages. The management is directed to re-instate him forthwith and pay him his back wages @ Rs. 5.65 p. per day ever since 15-3-74 and treat him continuous on duty. An award is made accordingly.

29th October, 1976.

[F. No. L-42012(37)/74-LR. III/D. II. (B)]

D. D. GUPTA, Presiding Officer

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1976

का०आ० 1752.—व्यास सतलुज लिंक प्रोजैक्ट के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 24 नवम्बर, 1976 को मिला था, प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

के बीच :

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले	श्री ओ०पी० गुप्ता, कार्मिक अधिकारी व्यास सतलुज लिंक प्रोजैक्ट सुन्दरनगर, टाउनशिप ।
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले	व्यास सतलुज लिंक वर्कर्स यूनियन, सुन्दरनगर, टाउनशिप (हिमाचल प्रदेश)

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री ओ०पी० सक्सेना, सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) बरेली के मध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है:—

1. विनिर्दिष्ट विवाद-ग्रस्त विषय :

"क्या व्यास सतलुज लिंक प्रोजैक्ट, सुन्दरनगर टाउनशिप के प्रबन्धतंत्र की श्री रवैल सिंह संवाहक, टोकन सं० 933 एफ० का वेतन 21-4-71 से प्रति माह 110 रु० पर निर्धारित करने और उन्हें नया कर्मचारी मानने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?"

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता सम्मिलित है ।	मुख्य अभियन्ता, व्यास सतलुज लिंक प्रोजैक्ट, सुन्दरनगर ।
3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम ।	व्यास सतलुज लिंक वर्कर्स यूनियन. सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश)
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	35,000
5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।	एक

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा। मध्यस्थ अपना पंचाट चार मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निवेश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

हस्त० (ओ०पी० गुप्ता)
9/11
कार्मिक अधिकारी,
व्यास सतलुज लिंक प्रोजैक्ट,
सुन्दरनगर, टाउनशिप

हस्त० (एन०पी० शर्मा)
9/11
महा मंत्री
व्यास सतलुज लिंक वर्क्स
यूनियन, सुन्दरनगर

साक्षी :

1. ह/० (रावैल सिंह)
2. ह/० (आर० एल० डोगरा)

[फा० संख्या एल-42012(27)/76 डी०2(बी०)]
हरबंस बहादुर, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 4th December, 1976

S.O. 4752.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of Beas Sutlej Link Project and its workmen represented by Beas Sutlej Link Workers' Union.

And, whereas the said employers and workmen have, by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 24th November, 1976.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Representing Employer—Shri O. P. Gupta, Personnel Officer, Beas Sutlej Link Project, Sundernagar Township.

Representing Workman—Beat Sutlej Link Workers' Union, Sundernagar Township (H.P.).

It is hereby agreed between the parties to refer the following Industrial Dispute to the arbitration of Shri O. P. Saksena, Assistant Labour Commissioner (C), Bareilly.

1. Specific matter in dispute :—

"Whether the action of the management of Beat Sutlej Link Project, Sundernagar Township in fixing Shri Rawail Singh, Conductor token No. 933-F at Rs. 110 P.M. w.e.f. 21-4-1971 and treating him as fresh employee was justified? If not, to what relief he is entitled?"

2. Detailed of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking	Chief Engineer, Beas Sutlej Link Project, Sundernagar.
3. Name of the Union, if any, representing the workman in question.	Beas Sutlej Link Workers' Union, Sundernagar (H.P.)
4. Total number of workmen employed in the undertaking effected.	35,000
5. Estimated numbers of workman effected or likely to be effected by the dispute.	One

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us. The arbitrator shall make his award within a period of four months or within such further time us is extended by mutual agreement by us in writing. In case the award is not made within the period afore-mentioned the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Sd/- (O. P. Gupta)
9/11
Personnel Officer,
Beas Sutlej Link Project,
Sundernagar Township.

Sd/- (N. P. Sharma)
9/11
General Secretary,
Beas Sutlej Link Workers' Union
Sundernagar.

Witnesses:—1. Sd/- (Ravail Singh)
2. Sd/- (R. L. Dogra)

[F. No. L-42012(27)/76-D.II(B)]
HARBANS BAHADUR, Desk Officer

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1976

का०आ० 4753.—केन्द्रीय सरकार, ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2119, तारीख 4 जून, 1976 द्वारा पाइराइट्स खनन उद्योग में सेवा को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 4 जून, 1976 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 4 दिसम्बर, 1976 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस० 11017/6/76-डी-1(ए)]
एल० के० नारायणन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th November, 1976

S.O. 4753.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section (2) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2119 dated the 4th June 1976, the service in Pyrites Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 4th June, 1976;

And whereas the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period for six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 4th December, 1976.

[No. S-11017/6/76/DI(A)]
L. K. NARAYANAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1976

का०आ० 4754.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विसोकेम (प्राइवेट) लिमिटेड, अटेल, पो०आ० मोहने, कल्याण, जिला

थाना, जिसमें (1) 23, फिरोजशाह मेहता रोड, पो०कं० सं० 436 मुम्बई-1 और (2) सबन भवन, 187, शेरिफ देव जी स्ट्रीट मुम्बई-3 स्थित इसके कार्यालय भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(55)/76 पी०एफ०-2(i)]

New Delhi, the 1st December, 1976

S.O. 4754.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in the relation to the establishment known as Messrs Visochem (Private) Limited, Atale, Post Office Mohane, Kalyan, District Thana, including its offices at (i) 23, Sir Phirozshah Mehta Roatl, Post Box No. 436, Bombay-1, and (ii) Saban Bhavan, 187, Sherief Davji Street, Bombay-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of January, 1975.

[No. S-35018(55)/76-PF.II(i)]

का०आ० 4755.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 जनवरी, 1975 से मैसर्स विसोकेम (प्राइवेट) लिमिटेड अटेल पो०आ० मोहने कल्याण, जिला थाना, जिसमें (1) 23 फिरोजशाह रोड, पो०आ० सं० 436 मुम्बई-1 और (2) सबन भवन, 187, शेरिफ देवजी स्ट्रीट मुम्बई-3 स्थित इसकी शाखाएं भी सम्मिलित है । नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018(55)/76-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 4755.—In exercise of the powers conefrred by the first proviso to section 6 of the Employees' Providen Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of January, 1975 the establishment known as Messrs Visochem (Private) Limited, Atale, Post Office Mohane, Kalyan, District Thana, including its branches at (i) 23, Phirozshah Mehta Road, Post Box No. 436, Bombay-1, and (ii) Saban Bhavan, 187, Sherief Devji Street, Bombay-3, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(55)/76-PF. II(ii)]

का०आ० 4756.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंजाब स्कूटर्स लिमिटेड, ग्राम ककाला, नाभा, जिला पटियाला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(420)/76-पी०एफ०-2]

S.O. 4756.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Punjab Scooters Limited, Village Kakrala, Nabha (District Patiala), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1976.

[No. S-35019(420)/76-PF. II]

का०आ० 4757.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रदीप इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, जी०टी० रोड फगवाड़ा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(416)/76-पी०एफ-2]

S.O. 4757.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pradeep Engineering Industries, G. T. Road, Phagwara, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1975.

[No. S-35019(416)/76-PF. II]

का०आ० 4758.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजा दिनेश टेक्सटाइल्स, चिरक्कल, चिरक्कल गांव, कन्नोर तालुक, कन्नोर जिला केरल, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(418)/76-पी०एफ०2]

S.O. 4758.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raja Dinesh

Textiles, Chirakkal, Chirakkal Village, Cannanore Taluk, Cannanore District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Ac, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1976.

[No. S-35019(418)/76-PF. II]

का०आ० 4759.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चिल्का लेक-आइस फैक्टरी यूनिट संख्या-2 पो०आ० बालुगांव, जिला पुरी, उड़ीसा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1973 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(419)/76-पी०एफ०-II]

S.O. 4759.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Chilka Lake Ice Factory Unit No. 2, Post Office Balugaon, District Puri, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S-35019(419)/76-PF. II]

का०आ० 4760.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राबिन केमिकल्स, प्राइवेट 1ए/4, नेलसन मनिका मुदालियर रोड, मद्रास-29 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(77)/76-पी०एफ०-II]

S.O. 4760.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Robin Chemicals, Private, 1A/4, Nelson Manicka Mudaliar Road, Madras-29, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1975.

[No. S-35019(77)/76-PF. II]

का०आ० 4761.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नवनशहर प्राइमरी कोआपरेटिव भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, नवनशहर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(417)/76-पी०एफ2(i)]

S.O. 4761.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Nawanshahar Primary Co-operative Land Mortgage Bank Limited, Nawanshahar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1976.

[No. S-35019(417)/76-PF. II(i)]

का०आ० 4762.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अगस्त, 1976 से मैसर्स नवनशहर प्राइमरी कोआपरेटिव भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, नवंमशहर नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस-35019(417)/76-पी०एफ-2(ii)]

S.O. 4762.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of August, 1976, the establishment known as Messrs. Nawanshahar Primary Co-operative Land Mortgage Bank Limited, Nawanshahar, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(417)/76-PF. II(ii)]

का०आ० 4763.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जनरल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, सातवां मील, होसूर रोड, बंगलोर-29 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(415)/76-पी० एफ०2]

S.O. 4763.—Whereas it appears to the Central Government ment that the emuloyer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs General Constructions Company, 7th Mile Hosure Road, Bangalore-29, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1976.

[No. S-35019(415)/76-P.F. II]

का०आ० 4764—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अशोक रेस्टोरेन्ट नाडियाड रेलवे स्टेशन के सामने, नडियाड, जिला० कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(247)/76-पी०एफ०2]

आर० एस० देशपांडे, उप सचिव

S.O. 4764.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ashok Restaurant, Opposite Nadiad Railway Station, Nadiad, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1974.

[No. S-35019(247)/76-P.F. II]

R. S. DESHPANDE, Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd December, 1976

S.O. 4765.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Dhori Colliery, Post Office Bermo, District Hazaribagh and Messrs Phusro Coal and Construction Company Bermo C/o Meghdoot Cinema, Phusro, Post Office Bermo, Dist., Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th November, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 35 of 1968

(Ministry's Order No. 1/34/67-LR.II dated the 2nd May, 1968)

PARTIES :

Employers in relation to the Dhori Colliery, Post Office Bermo, District Hazaribagh.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers (Central Coalfields Ltd.)—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen—Shri P. K. Bose.

State : Bihar Industry : Coal

Dhanbad, the 22nd November, 1976

AWARD

M/s. Bokaro and Ramgarh Limited were the quendam owners of the Dhori Colliery comprising an area of 10,061 standard bighas. M/s. Sarangarh Coal Company were their Raising-cum-Selling Contractors in respect of the entire Dhori Colliery comprising the area aforesaid. The Raising-cum-Selling Contractors appointed M/s. Phusro Coal and Construction Company as their Sub-Raising-cum-Selling Contractors in respect of 42 : 16 bighas, being a portion of the Dhori Colliery, commonly known as Karo East quarries Nos. 2, 3 and 4. The Regional Inspector of Mines informed M/S. Bokaro and Ramgarh Limited by his letter Ext. M-1 dated April 24, 1967 that the said quarries were situated within the lightest flood level of a nallah and as mining work shall be undertaken in the said quarries during the rainy reason, that is to say, between June 15 and October 31, 1967. The sub-contractors (Phusro Coal and Construction Company) pasted a notice on their Notice Board on June 1, 1967 that the Regional Inspector of Mines had declared the said quarries as seasonal in character in as-much-as no work can be done therein between June 15 to October 31, 1967 and, therefore, the entire lot of workmen—292 in number—will be laid-off during the said period and no lay-off compensation would be admissible to them under Section 25-C of the Industrial Disputes Act, read with Section 25-A-(1)(b) of that Act. The Vice President, Colliery Mazdoor Sangh, and the Secretary, Koyala Mazdoor Panchayat, raised an industrial dispute with regard to the said lay-off and refusal to pay compensation therefor and when the dispute was not resolved, the Vice President, Colliery Mazdoor Sangh, approached the conciliation machinery for the settlement of the dispute. The Assistant Labour Commissioner (Central), Hazaribagh hold the conciliation proceedings but this resulted in a failure, and he submitted his failure report to the Central Government on September 5, 1967.

2. The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, thereupon referred the following dispute for adjudication to this Tribunal, namely :—

> "Whether the managements of Dhori Colliery, Post Office Bermo, District Hazaribagh and M/s. Phusro Coal and Construction Company, Post Office Bermo are justified in laying-off 292 workmen from Karo East Quarries Nos. 2, 3 and 4 with effect from the 15th June, 1967, without paying any lay-off compensation? If not, to what relief are the workmen entitled?"

3. Usual notices were issued to the parties concerned to file their respective statement of claim; and in pursuance of that, M/s. Phusro Coal and Construction Company and the Manager of the Dhori Colliery filed their written statements on December 3, 1968, the Koyala Mazdoor Panchayat on December 10, 1968, and the Colliery Mazdoor Sangh on June 6, 1969. The Manager, Dhori Colliery, filed his rejoinder to the written statement of the Koyala Mazdoor Panchayat on December 27, 1968 and M/s. Phusro Coal and Construction Company filed their rejoinder to the same written statement on January 21, 1969. The Manager, Dhori Colliery filed his rejoinders to the written statement of the Colliery Mazdoor Sangh on July 16, 1969 and March 7, 1970. The Phusro Coal and Construction Company Ltd. filed their rejoinders to the written statement of the Colliery Mazdoor Sangh on March 7, 1970 and February 8, 1971. The Dhori Colliery is a coking

coal colliery. It was under the management of a Receiver appointed by the Sub-Judge, Hazaribagh. In terms of the Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Ordinance, 1971, the Bharat Coking Coal Ltd. took over the management of the colliery as Custodian on August 16, 1972. Coking coal mines were nationalised with effect from May 1, 1972 under the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972. The Bharat Coking Coal Ltd. then entrusted the management of the colliery to the National Coal Development Corporation and the Corporation entrusted it finally to the Central Coalfields Limited on November 1, 1975. It is in these circumstances that the Central Coalfields Limited was also made a party to the reference under section 18(3)(b) of the Industrial Disputes Act. The Central Coalfields Limited filed their written statement on August 30, 1976.

4. M/s. Phusro Coal Construction Company have, in their written statement, pleaded that the 292 workmen were laid-off during the period June 15 to October 31, 1967 on the order of the Regional Inspector of Mines and not on account of their own volition and as such the lay-off does not amount to lay-off, within the meaning of the Industrial Disputes Act and the aforesaid workmen are not entitled to any compensation for lay-off effected under a statutory order and not on the basis of any action on their own part.

5. The Manager, Dhori Colliery has pleaded that the reference is incompetent because there was no industrial dispute in as much as (i) the union had not made any demand for payment of lay-off compensation on the management, (ii) the conciliation proceedings cannot convert the dispute into an industrial dispute and (iii) the dispute before the conciliation officer was only regarding lock-out and not for compensation for lay-off and, therefore, the present reference regarding compensation for lay-off is a new dispute which was not agitated during the course of conciliation proceedings. He has then pleaded that the 292 workmen were the employees of M/s. Phusro Coal and Construction Company and the relationship of employer and employees subsisted between them and not between the workmen and the Dhori Colliery and, therefore, the Dhori Colliery is not responsible for any lay-off or for any compensation for that. He has also pleaded that the Regional Inspector of Mines had declared the said quarries as of seasonal character under Section 25A(1)(b) of the Industrial Disputes Act and, therefore, Section 25-C which provides for payment of lay-off compensation becomes inapplicable.

6. The Koyala Mazdoor Panchayat has pleaded that the actual owners of the said quarries were M/s. Bokaro and Ramgarh (Pvt.) Limited and the Contractors M/s. Sarangarh Coal Company and the Sub-contractors M/s. Phusro Coal and Construction Company were mere shadows established to subvert the provisions of the statute and the relationship of employer and employees existed between the actual owners and the workmen and not between M/s. Phusro Coal and Construction Company and the workmen. The Panchayat has then pleaded that if the Regional Inspector of Mines had directed the suspension of work on account of apprehended inundation, the remedy open, was to retrench the workmen and to pay retrenchment compensation to them under Section 25-F and not to lay-off them. It has also pleaded that the quarries in question are not of seasonal character within the meaning of Section 25-A(1)(b) and, therefore, compensation is payable under Section 25C. Its last plea is that the lay-off amounts to an unfair labour practice and the workmen are entitled to full compensation.

7. The Colliery Mazdoor Sangh has not raised any new plea. It has reiterated the pleas taken by the Colliery Mazdoor Panchayat and, therefore, it is not necessary to repeat the pleas.

8. The Central Coalfields Limited has pleaded that the Dhori Colliery has vested in the Central Government free from all incumbrances under Section 9 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act and no award can either be passed or enforced against it in relation to any matter anterior to May 1, 1972.

9. The various rejoinders referred to above do not cover any new grounds and no further mention of these rejoinders is, therefore, called for.

10. The only contest raised by the Manager, Dhori Colliery and M/s. Phusro Coal and Construction Company is that quarries Nos. 2, 3 and 4 constitute an industrial establishment which is of a seasonal character and, therefore, Sections 25-C to 25-E shall not apply to such an establishment. There can be no manner of doubt that if an industrial establishment falls under Sec. 25-A(1)(b), this Tribunal will have no jurisdiction to award lay-off compensation to the workmen of such an establishment. Section 25-A(2), however, provides that if a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character, the decision of the appropriate Government thereon shall be final. The Tribunal has no jurisdiction to decide the question whether an industrial establishment is of a seasonal character or not. In view, of this, the dispute was referred to the Central Government, which is the appropriate Government, in respect of a mine, and the decision of the Central Government was communicated to the Tribunal by their letter No. 1/34/67-LRII dated October 7, 1974 to the effect that it had not declared the quarries in question as seasonal in the year 1967. This being the decision of the Central Government, the Contention of the Dhori Colliery and M/s. Phusro Coal and Construction Company that no lay-off compensation is payable, falls to the ground.

11. The next point raised by the Manager, Dhori Colliery and by M/s. Phusro Coal and Construction Company is that neither the union, nor the workmen, had made any demand on the management for lay-off compensation and, therefore, no industrial dispute arose or existed which the Central Government could refer to this Tribunal for adjudication. The union has examined Kannhya Singh WW-1 to prove that an industrial dispute was raised, and he has deposed that such a dispute was raised with the management but they were adamant in their attitude and replied that mining operations will remain closed and the workmen will be given work again when operations were started on November 1, 1966. The Manager of the Dhori Colliery and M/s. Phusro Coal and Construction Company have not appeared to challenge or controvert this statement of Kannhya Singh. I, therefore, held that an industrial dispute had been raised and existed and the Central Government was competent to make the reference.

12. The third contention of the Manager, Dhori Colliery and M/s. Phusro Coal and Construction Company is that they had no hand in declaring the lay-off and they had to do it not on their own volition but under a statutory order passed by the Regional Inspector of Mines under Section 22 of the Mines Act. The order purports to have been passed under sub-section (2) of section 22 of the Mines Act which provides that the Chief Inspector or the premature collapse of any part of the workings or the owner, agent or manager of a mine, prohibit the extraction or reduction of pillars or blocks of minerals in any mine or part thereof, if, in his opinion, such operation is likely to cause the crushing of pillars or blocks of minerals or the premature collapse of any part of the workings or otherwise endanger the mine or the life or safety of persons employed therein or if, in his opinion, adequate provision against the out-break of fire or flooding has not been made by providing for the sealing of and isolation of the part of the mine in which such operation is contemplated and for restricting the area that might be affected by fire or flooding. The reason given by the Regional Inspector of Mines was that the quarries in question were situate within the highest flood level of a rivulet and, therefore, work had to stop. Nothing prevented the Manager, Dhori Colliery or M/s. Phusro Coal and Construction Company from isolating the part of the quarries from the ravages of the rivulet by the construction of an embankment. Likewise, the order did not say that the workmen must be lai-off. I am of the view that the lay-off actually declared is covered by the definition of lay-off under clause (kkk) of section 2 of the Industrial Disputes Act. There will be a lay-off if there is failure, refusal or inability on the part of an employer to give work to his workmen if such failure, refusal or inability is on account of either shortage of coal, power or raw material, or accumulation of stock or break-down of machinery or any other reason. Obviously, there was no shortage of coal, power or raw materials and there was no accumulation of stocks or break-down of machinery. The question, however, is whether the lay-off was due to "any other reason". The words "any other reason" indicate that there must be a reason which is allied or analogous to the other reason aforesaid. In other wards, these words have to be construed ejusdem generis with the words that precede them. Advantage in this regard may be had from the decisions of their Lordships of the Supreme Court in Kairbetta Estate vs. Rajamanickam, 1960 (II)LLJ. 275 and Workmen of Dewan Tea

Estate vs. Management, 1964(I)(LLJ. 358. A statutory order for stopping mining operations is, to my mind, ejusdem generis to the other grounds given in sub-section (kkk). I have no doubt therefore, in my mind, that there was a lay-off within the said clause. I have already stated above that these quarries were not seasonal in character. The appropriate Government has already taken a decision to that effect. Section 25-C will, therefore, have application. The 292 workmen, it has not been challenged, were in continuous service for a period of one year preceding June 15, 1967, within the meaning of Section 25-B. They shall be paid compensation for a period of 45 days, which shall be equal to 50 per cent of their total basic wages and dearness allowance that would have been payable to them, had they not been so laid-off. In accordance with the first proviso to Section 25-C, no such componsation is payable in respect of any period of the lay-off after the expiry of first 45 days if there is an agreement to that effect between the workmen and the employer. There is an agreement to the contrary contained in clause 25 of the Certified Standing Orders. Clause 25 says that the Company may at any time or times in the event of underground trouble, fire, catastrophe, break-down of machinery or stoppage of power supply, epidemics, civil commotion, or other cause beyond the control of the Company stop any section or sections of the Colliery wholly or partially, for any period or periods without notice and without compensation in lieu of notice. The lay-off was beyond the control of the Company and therefore, this clause contains an agreement to the contrary. Of course, it cannot totally take away the sting of Section 25-C but this clause falls under the first proviso and, therefore, compensation shall be payable only for the first 45 days and not for the entire period covered by June 15, 1967 to October 31, 1967.

13. The workmen are entitled to lay-off compensation for 45 days only and at 50 per cent of the total of their basic wages and dearness allowance that would have been payable to them had they not been laid-off on June 15, 1967. The liability for the payment is that of Bokaro and Ramgarh Ltd., M/s. Sarangarh Coal Company and M/s. Phusro Coal and Construction Company. The Central Coalfields Ltd. is not liable for the lay-off compensation anterior to the period May 1, 1972.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-1/34/67-LR II/D. III(A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 24th November, 1976

S.O. 4766.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Gawan Mica Mining Company Limited, Post Office Domchanch, District Hazaribagh, Mica Mine Owners and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd November, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 9 of 1974

(Ministry's Order No. L-28011/6/74-LR. IV dated, the 26th June, 1974)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs Gawan Mica Mining Company Limited, Post Office Domchanch, District Hazaribagh, Mica Mine Owners and their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri Mahinder Singh, Advocate with Shri Maheswari Prasad Singh.

For the Workmen.—Shri J. D. Lal, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Mica.

Dhanbad, the 20th November, 1976

AWARD

Messrs Gawan Mica Mining Co. Ltd. (hereinafter referred to as the Company) paid the statutory minimum bonus at eight and one-third per cent of the wages earned by its workmen to them for the calender year 1972. The Metalliferous Mine Workers Association (hereinafter referred to as the Association) raised an industrial dispute with the Assistant Labour Commissioner (Central), Hazaribagh by its letter No. MMWA/86/74 dated March 1, 1974 demanding payment of bonus at 20 per cent of the salary for the said year. The matter was taken up in conciliation proceedings with the result that the Assistant Labour Commissioner submitted a failure report to the Central Government on April 27, 1974.

2. The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act has consequently referred the following dispute for adjudication to this Tribunal, namely,

> "Whether the demand of the workmen employed by Messrs Gawan Mica Mining Company Limited, Post Office Domchanch, District Hazaribagh, Mica Mine Owners for payment of bonus @20 per cent instead of 8-1/2 per cent of the wages earned by them for the accounting year commencing in 1972 is justified ? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled to for that year ?"

3. Usual notices were issued to both the parties to file their respective written statements ; and in response to that, while the Company filed its written statement on January 10, 1975 and a supplementary written statement on August 2, 1976, the Association filed a rejoinder only to these two written statements on August 26, 1976.

4. The claim of the Association for payment of bonus at the maximum rate of 20 per cent, has been resisted by the Company on various grounds, namely, (1) the floor price of mica was fixed in the year 1964 and though since then labour wages, cost of materials used in mining operations and other expenses of mining operations have gone up by 300 to 400 per cent, the floor price is still the same, (ii) the Mica Industry is facing the risk of closure on account of severe financial crisis, (iii) all surface deposits of mica have completely exhausted and deep mining has become costly and un-economical, (iv) mining operations are interruppted due to non supply of electricity or frequest breakdowns in the supply, (v) production has also gone down because of strike and go-slow tactics adopted by labour, and (vi) the Company has incurred a loss during the calendar year in question, and that, on the totality of all these facts, it is not in a position to pay anything beyond the statutory minimum, which it has already paid to its workmen. Some legal pleas have also been raised, namely, that the Association never made any demand for higher bonus on the Company and, therefore, there was no industrial dispute which could be referred by the Central Government to the Tribunal for adjudication. With regard to the conciliation proceedings, the averment made is that the Company was not afforded any opportunity by the Assistant Labour Commissioner to oppose the demand of the Association and on that ground also, there was no industrial dispute.

5. The only additional points raised by the Company in its supplementary written statement, are that the Association is not a recognized union and can have no right to espouse the cause of the workmen ; that it took over the management of the mine only on June 23, 1972 and, therefore, it cannot be saddled with the payment of bonus for the entire year ; and that a settlement was arrived at between the Company and its workmen for payment of minimum bonus only and so long that settlement is in force, the present claim for higher bonus is not maintainable.

6. It is unfortunate that the Association did not file a written statement, giving the basis of its claim for payment of the maximum bonus. In its rejoinder, the facts are so

scanty that no head and tail can be made out of it as to the grounds on which the maximum bonus is claimed. The only thing alleged is that the Company's allegations of incurring a loss, or increase in labour wages, or in the cost of materials, or in the expenses on the mining operations, or about go-slow tactics or strike, are false. The settlement put forward by the Company has been controverted on the ground that it is not binding on the Association because it was not a party to it.

7. The only points that were canvassed before me were (i) the validity or otherwise of the reference, (ii) the validity and binding nature or otherwise of the settlement, and (iii) the justification or otherwise of an increase in the rate of bonus. No other points were pressed.

8. It would be better to dispose of the two preliminary points first, before entering into the merits of the claim for higher bonus.

9. In Sindhu Resettlement Corporation Ltd. vs. Industrial Tribunal, 1968 (I)LLJ. 834, the Supreme Court has laid down that a more demand to the appropriate Government without a dispute being raised by the workmen with their employer regarding such demand, cannot become an industrial dispute. A Division Bench of the Delhi High Court has followed the principles of Sindhu Resettlement case in Fedders Llyod Corporation (Pvt.) Ltd. vs. Lt. Governor, 1970 Lab. I.C. 421 and observed that a demand by the workmen must be raised first on the management and rejected by them before an industrial dispute can be said to arise and exist and that making such demand to the conciliation officer and its communication by him to the management, who rejected to demand is not sufficient to constitute an industrial dispute. A Division Bench of the Patna High Court has taken the view in Management of Radio Foundation Engineering Limited vs. State of Bihar AIR 1970 Pat. 295, that a dispute about the reason for stoppage of work where the workmen stopped the work according to the employer, while according to the workmen they were not allowed to work due to closing of the place of employment and the suspension of work was an industrial dispute despite the fact that no specific demand by the workmen was made in this connection. It was held that no specific demand by the workmen was necessary to bring about the existence of an industrial dispute on the facts and in the circumstances of the case. The learned counsel for the Company has placed reliance upon the first two, while the learned counsel for the Association has pinned his faith on the third case. The third case was decided on its own peculiar facts. It was distinguished by another Division Bench of the same High Court in Management of Nund and Sament Co. vs. Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in C.W.J.C. No. 45 of 1975 decided on August 16, 1976 and it was held that if the demand is made not with the management but with the Assistant Labour Commissioner and the latter communicates the demand to the management that will not amount to making the demand upon the management, and there will be no industrial dispute in the circumstance.

10. The learned counsel for the Association, however, invited my attention to Section 22 of the Payment of Bonus Act and argued that under this section a demand regarding payment of bonus shall be deemed to be an industrial dispute, irrespective of the fact whether such a demand was made upon the management and rejected by it or not. I do not think that this is the interpretation which can be placed on this section. The meaning to be assigned to it is clear from the decision of the Supreme Court in Sanghvi Jeevraj Ghowar Chand vs. Madras Chillies, Grains and Kirana Merchant's Workers Union, 1969 (I) LLJ. 719. The Supreme Court observed that Section 22 provides that where a dispute arises between an employer and his employees with respect to the bonus payable under the Act, such a dispute shall be deemed to be an industrial dispute within the meaning of the Industrial Disputes Act and the provisions of that Act shall, save as otherwise expressly provided, apply accordingly. An industrial dispute under the Industrial Disputes Act would be between a workman as defined in that Act and his employer and the dispute can be an industrial dispute if it is one as defined therein. But the definition of an "employee" under Section 2(13) of the Payment of Bonus Act is wider than that of a "workman" under Industrial Disputes Act. A question between an employer and an employee, therefore, may not fall under the Industrial Disputes Act and in such a case the Act would not apply and its machinery for investigation and settlement would not be available. That being so, in order that such machinery for investigation and settlement may be available, Section 22 has been enacted to create a legal friction whereunder such disputes are deemed to be industrial disputes under the Industrial Disputes Act. It is clear, therefore, that the deeming clause has been inserted in Sec. 22 to enable a dispute which is not an industrial dispute to become one. The section does not dispense with the general law that in order to constitute a dispute as an industrial dispute, a demand must be made on the management and rejected by it. I am of the view, therefore, that the reference is not competent.

11. The settlement relied upon by the Company is material Ext. 2. It was arrived at during conciliation proceedings on 12-9-1966 between the workmen of mica mines represented by Mica Labour Union, ABRAKH Mazdoor Union and Abrakh Mazdoor Panchayat and their employers on the issue of payment of bonus. Under the settlement, the employers agreed to pay to their workmen 4% of the total salary or wages or Rs. 40 whichever was higher as bonus for the accounting years 1964, 1965, 1966 and 1967. The settlement does not fix any period during which it will be in force and no notice for its revocation was given. I will, however, not attach any significance to this agreement for several reasons. Firstly, it was made clear to the Company that the original must be produced but no attempt was made to produce the original and prove the material Ext. Besides, the certified copy of the judgement of the Patna High Court shows that this settlement was superseded by another one dated February 7, 1972. This second settlement has not been produced to show that the Association was a party to it and, therefore, the contention of the learned counsel for the Association has force that the settlement is not binding on it.

12. Sections 4, 5, 6 and 7 together with the Second Schedule deal with the computation of "gross profits" and "available surplus" out of which 67 per cent in cases falling under clause (a) of Sec. 4 would be "allocable surplus" as defined in Sec. 2(4). Sec. 2(18) defines "gross profits" to mean the gross profits calculated under Sec. 4 read with the Second Schedule. The basis is the net profit as shown in Profit and Loss Account after making usual and necessary provisions and certain additions are made to it as provided in Sec. 4 to compute profits and then out of the said gross profits certain deductions are to be made as provided in Sec. 6 and Third Schedule with a view to ascertain the available surplus. Out of the available surplus, the "allocable surplus" is calculated and then the bonus payable to the workmen is computed, in accordance with the other provisions of the Act. The Association has not produced any document to enable the Tribunal to find out if there is any "allocable surplus". It did not even summon the books of account of the Company for that purpose. It only examined WW-1 Biren Ray and WW-2 Jhari to establish that there was an "allocable surplus" but they have cut a very sorry figure and do not know if the Company has earned a profit or incurred a loss in the year 1972. As against this, the Company has produced its Balance-Sheet and Profit and Loss Account to show that there was a loss of Rs. 1,23,313.29 in that year. The accounts were audited by Bhotica and Co. who are Chartered Accountants. The Auditors had obtained all the informations and explanations which were necessary for the purpose of their audit; and they have given the opinion that proper books of accounts had been kept by the Company; and the Balance-Sheet and Profit and Loss Account were in agreement with the books of accounts, subject to their notes Nos. 4, 5, 6 and 9. Sec. 23 of the Payment of Bonus Act raises a prima facie presumption about the accuracy of the statement and particulars contained in the Balance-sheet and Profit and Loss Account of a Company which is duly audited by qualified Auditors of the Company under Sec. 226(1) of the Companies' Act. There is no reason why I should not regard the Balance-Sheet and Profit and Loss Account to be correct. It is true that the presumption indicated by the Section is not conclusive but is rebuttable. However, the Association did not raise any dispute regarding its accuracy at the relevant time. It was only during the course of arguments that an attempt was made to show that certain items of expendiure were not correct, but there was no basis for this criticism. It is true that the Auditor had raised certain objections but they related to matters which are not relevant for the present purpose.

13. The Company owns certain mica mines situate at Khirkia, Saimandua and Athgorwa. This is admitted on both sides, vide statements of WW-1 Biren Ray, WW-2 Jhari and MW-1 Bipin Behari Ambastha. I am certain that the Company passed through a period of crisis during the year 1972. Electricity supply was erratic and there were frequent break-downs. This used to happen for a period ranging from 4 to 10 days every month; and whenever there was failure in supply, the mining operations used to come to a halt. The mine would get innundated with water because electric pumps would not work to drain out the water and enable mining operations to re-start. This is evident from the deposition of WW-1 Biren Ray and MW-1 Bipin Behari Ambastha. The Khirkia mine remained closed for a major part of the year. WW-1 Biren Ray even admitted that it remained closed for the whole year. WW-2 Jhari stated that the Company wanted to undertake deep mining in Khirkia but no mica was present in depth and then it started extraction in stopping blocks. Extraction in stopping blocks commenced after seven months attempt to extract mica by deep mining had failed. Jhari further admitted that Athgorwa remained closed for about three years because the Company stopped mining there even though mica was present. The Company never worked the Rahri Mine. He further admitted that the Company took the management of the Khirkia mine in May or June, 1972 but work had to be stopped because lifts had to be fixed. He went on to admit that there was no production of mica in Khirkia mine for about a year. MW-1 Bipin Behari deposed that Khirkia mine was closed because of a direction issued by the Director-General of Mines Safety under Sec. 22 of the Mines Act. MW-2 Bharat Prasad Singh stated that the ban on mining operations was lifted on November 23, 1972. WW-1 Biren Ray and WW-2 Jhari have no knowledge as to the extent of the production in the Company's mines in 1972. They have also no idea if the Company earned a profit or incurred a loss in that year. In the circumstances, therefore, there is no evidence before me to show that there was any "allocable surplus" and consequently the workmen are not entitled to any bonus beyond the statutory minimum which has already been paid.

14. The award is that the demand of the workmen for payment of bonus over 8.33 per cent of their wages for the accounting year 1972 is not justified and they are not entitled to any bonus beyond the statutory minimum which has admittedly been paid to them.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-28011(6)/74-LR. IV/D. IV(B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O. 4767.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the management of the Allahabad Bank, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 3-12-76.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 11 of 1976

Employers in relation to the Allahabad Bank,

AND

Their workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers—absent.

On behalf of Workmen—Sri Ashok Kumar Singh, Organising Secretary, All India Allahabad Bank Employees' Association.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking

AWARD

By order No. L-12012/133/75-D-IIA dated 26th February, 1976 the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the Allahabad Bank and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The Reference reads as :

"Whether the action of the management of Allahabad Bank, Calcutta in denying Shri R. N. Kakkar, Assistant Head Cashier, the posting at Southern Avenue Branch of the said Bank on promotion is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The contention on behalf of the workmen is that the employer Allahabad Bank discriminated against Ram Narayan Kakkar in transferring him to North Barrackpore branch on promotion to the post Head cashier, C grade instead of transferring him to Southern Avenue Branch, Calcutta. According to the union which sponsored the workman's cause, both the Siliguri and North Barrackpore branches were upgraded with effect from 1.1.1974 where the Head cashier's posts in C grade were to be filled up. But the management did not post either Sri R. P. Tandon or Sri J. P. Tandon to those posts. Under the rules made by the management, the senior most men should have been posted to the vacancies which occured first. According to the union the Southern Avenue branch vacancy of Head cashier C grade came into existence with effect from 7-6-1974 when the branch was upgraded for that post. However, the management appointed J. P. Tandon to Southern Avenue Branch and R. N. Tandon to Chowringhee branch, Calcutta though the latter was upgraded on 17-4-74. Accordingly, the union stated that Sri Kakkar should be posted to Southern Avenue branch, Calcutta as he is the junior most of all the Assistant Cashiers.

3. This reference was contested by the management on filing a written statement. But when the reference was taken up for hearing, there was no person present before the Tribunal for and on behalf of the Bank. So, the bank was declared ex-parte.

4. The workman Sri R. N. Kakkar was examined as WW-1. His evidence is that both R. P. Tandon and J. P. Tandon are seniors to him and that they were seniors were seen from Ext. W-2, seniority list. On the basis of clause (f) of Ext. W-1 circular of the Bank the promotion shall be on seniority basis. The evidence was that both R. P. Tandon and J. P. Tandon being the seniors in the cadre of Assistant Cashiers they should have been posted to Siliguri and North Barrackpore branches which were upgraded with effect from 1-1-1974. There is evidence that Sri R. K. Agarwal who is senior to R. N. Kakkar had been posted at Siliguri on the basis of mutual transfer So, he did not oppose the appointment of R. K. Agarwal. There was no ground for the management to have appointed R. N. Kakkar on the basis of Ext. W-3 order dated 12-6-75 to North Brarackpore branch when Southern Avenue branch was available for his appointment with effect from 7-6-74. The appointment on promotion in respect of R. N. Kakkar to North Barrackpore branch as per Ext. W-3 cannot therefore be justified. Evidently, some discrimination was seemed to have been shown against R. N. Kakkar in not transferring him to Southern Avenue branch in Calcutta when it was upgraded with effect from 7-6-74. So, the transfer order as per Ext. W-3 has to be set aside. He is also to be paid the monetary benefits which he would be entitled to get with effect from 7-6-74.

5. In the resulting, an Award is passed setting aside the transfer order as per Ext. W-3 and directing the management to post Sri R. N. Kakkar to Southern Avenue Branch with immediate effect. He is to be paid all the monetary benefits to which he would be entitled with effect from 7-6-1974.

Dated, Calcutta,

The 27th November, 1976.

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

[F. No. L-12012/133/75-DIIA]

R. P. NARULA, Under Secy.

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4768.—भारत के उपराष्ट्रपति, पंजाब विश्व-विद्यालय, चंडीगढ़ के कुलाधिपति के नाते पंजाब विश्व-विद्यालय अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1)(जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को नवम्बर 1, 1976 से 4 साल की अवधि के लिए साधारण पार्षद् मनोनीत करते हैं:—

1. डा. अखलाक आर. किदवाई, चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 8 सफदरजंग लेन, नई दिल्ली ।
2. अजीत राम वर्मा, डारेक्टर, नेशनल फिजीकल लेबोट्री, हिल साइड रोड, नई दिल्ली ।
3. श्री आदित्य प्रकाश, प्रिंसिपल, चंडीगढ़ कालेज आफ आरकिटेक्चर, चंडीगढ़ ।
4. श्री अमर नाथ विद्यालंकार, मेम्बर पार्लियामेन्ट, 87 शाहजहां रोड, नई दिल्ली ।
5. श्री बी. एम. पाटिल, एम.एल.सी., जनरल सेक्रेटरी, बिजापुर लाइब्रेल एजूकेशन सोसायटी, अक्कामहादेवर रोड, 4 बिजापुर ।
6. डा. बी. एन. गोस्वामी, प्रोफेसर आफ हिस्ट्री आफ आर्ट एण्ड हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट आफ फाइन आर्टस्, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ।
7. श्री बूटा सिंह, डिप्टी रेलवे मिनिस्टर, 19, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
8. डा. भुवन चन्देल, रीडर-इन-फिलास्फी, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ।
9. श्री दिलगंज सिंह जौहर, 674, सैक्टर 8-बी, चंडीगढ़
10. दि डीन आफ स्टूडेन्टस वैलफियर, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ।
11. दि डीन आफ यूनिवर्सिटी, इन्सट्रक्शन, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ।
12. डा. डी. सुन्दरसेन, डारेक्टर, नेशनल डेरी रिसर्च इन्सटीट्यूट, करनाल ।
13. श्रीमती गुरबरेन्द्र कौर बरार, मिनिस्टर आफ स्टेट फार हाउसिंग, पंजाब, सिविल सेक्रेट्रियट, चंडीगढ़ ।
14. जस्टिस गुरुदेव सिंह, रिटायर्ड जज, पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट, 540, सेक्टर 8-बी, चंडीगढ़ ।
15. डा. हरिकिशन सिंह, प्रोफेसर एण्ड हेड, डिपार्टमेन्ट आफ फारमाक्यूसिल साइंसिज, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ।
16. जस्टिस एच. आर. सोंधी रिटायर्ड जज, पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट, 34, सेक्टर-4, चंडीगढ़ ।
17. मिस जसवंत कौर, प्रिंसिपल, गवरमेन्ट कालेज फार ओमेन, चंडीगढ़ ।
18. श्री जग मोहन सिंह कांग, कोठी नं. 1539, सेक्टर-18, चंडीगढ़ ।
19. डा. एल. एच. लोबो, प्रिंसिपल, क्रिस्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना ।
20. श्री मुबारक सिंह, 44 माडल टाउन, अमृतसर ।
21. डा. मन मोहन सिंह, चीफ इकोनोमिक एडवाइजर, गवरमेन्ट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स, नई दिल्ली ।
22. डा. एम. सन्तापा, डारेक्टर, सेन्ट्रल लैदर रिसर्च इन्सटीट्यूट, मद्रास ।
23. श्री एन. डी. ग्रोवर, प्रिंसिपल, डी.ए.वी. कालेज, आबोहर ।
24. डा. ओ. पी. विग, प्रोफेसर एण्ड हेड, डिपार्टमेन्ट आफ कैमिस्ट्री, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ।
25. श्रीमती ओम प्रभा जैन, 'गिरिनार' 43/1, राजपुर रोड, दिल्ली ।
26. श्री प्रीतपाल सिंह गरेवाल, प्रिंसिपल गुरुनानक इंजिनियरिंग कालेज, लुधियाना ।
27. श्री पी. एल. टंडन, डारेक्टर जनरल, नेशनल कौंसिल आफ एप्लाईड इकोनोमिक रिसर्च, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली ।
28. प्रोफेसर रशीदुद्दीन खां, मेम्बर पार्लियामेन्ट, सी-1/13, पंडारा पार्क, नई दिल्ली ।
29. श्री आर. एस. चितकारा, (रिटायर्ड डारेक्टर यूनिवर्सिटी एजूकेशन, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन एण्ड सोसियल वेलफियर) बी-2/59, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली ।
30. जस्टिस आर. पी. खोसला, रिटायर्ड जज, पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट, 305, सेक्टर 10-बी, चंडीगढ़ ।
31. श्री सुधाकर पाण्डेय, मेम्बर पार्लियामेन्ट, 42, अशोका रोड, नई दिल्ली ।
32. डा. शिव दयाल, मेहरचन्द महाजन, प्रोफेसर एण्ड हेड, डिपार्टमेन्ट आफ लाज, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ।
33. डा. एस. सी. दूबे, डारेक्टर, इण्डियन इन्सिटीट्यूट आफ एडवान्सड स्टडी, शिमला ।
34. डा. केवल कृष्ण धीर, लेकचरार-इन-बोटनी, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ।

[सं. 10-वीसी/डीएस]

वि. फड़के, भारत के उपराष्ट्रपति

एवं पंजाब विश्व-विद्यालय के कुलाधिपति के सचिव

VICE-PRESIDENT SECRETARIAT

New Delhi, the 1st December, 1976

S.O. 4768.—The Vice-President of India, in his capacity as Chancellor of the Panjab University, Chandigarh, in exercise of his powers under Sub-Section 1 (j) of Section 13 of the Panjab University Act, is pleased to nominate the following as Ordinary Fellows of the Panjab University for the term commencing November 1, 1976 for a period of four years:—

1. Dr. Akhlaq R. Kidwai, Chairman, Union Public Service Commission, 8, Safdarjung Lane, New Delhi. ;

2. Dr. Ajit Ram Verma, Director, National Physical Laboratory, Hillside Road, New Delhi. ;

3. Mr. Aditya Prakash, Principal Chandigarh College of Architecture, Chandigarh;

4. Mr. Amar Nath Vidyalankar, Member Parliament for Chandigarh, 87, Shahjahan Road, New Delhi ;

5. Mr. B. M. Patil, M. L. C. General Secretary Bijapur Liberal Education Society, Akkamahadevi Road, Bijapur-4;

6. Dr. B. N. Goswamy, Professor of the History of Art, & Head of the Department of Fine Arts, Panjab University, Chandigarh ;

7. Mr. Buta Singh, Member of Parliament, (Dy. Rly. Minister) 19-Ferozeshah Road, New Delhi ;

8. Dr. (Miss) Bhuvan Chandel, Reader in Philosophy, Panjab University, Chandigarh ;

9. Mr. Diljang Singh Jauhar, 674, 8|B, Chandigarh ;

10. The Dean of Students' Welfare, Panjab University, Chandigarh ;

11. The Dean of University Instruction, Panjab University, Chandigarh ;

12. Dr. D. Sundresan, Director, National Dairy Research Institute, Karnal ;

13. Smt. Gurbinder Kaur Brar, Minister of State for Housing, Panjab, Civil Secretariat, Chandigarh ;

14. Justice Gurdev Singh, Retired Judge, Panjab & Haryana High Court, 540, Sector 8|B, Chandigarh ;

15. Dr. Harkishan Singh. Professor & Head, Department of Pharmaceutical Sciences, Panjab University, Chandigarh ;

16. Justice H. R. Sodhi, Retired Judge, Panjab & Haryana High Court, 34, Sector 4, Chandigarh ;

17. Miss Jaswant Kaur, Principal, Government College for Women, Chandigarh ;

18. Mr. Jagmohan Singh Kang, Kothi No. 1539, Sector 18, Chandigarh ;

19. Dr. L. H. Lobo, Principal, Christian Medical College, Ludhiana ;

20. Mr. Mubarak Singh, 44, Model Town, Amritsar ;

21. Dr. Manmohan Singh, Chief Economic Adviser, Government of India, Ministry of Finance, New Delhi ;

22. Dr. M. Santapa, Director, Central Leather Research Institute, Madras ;

23. Mr. N. D. Grover, Principal DAV College, Abohar ;

24. Dr. O. P. Wig, Professor & Head, Department of Chemistry, Panjab University, Chandigarh ;

25. Smt. Om Prabha Jain, 'Girnar', 43/1 Rajpur Road, Delhi.

26. Mr. Pritpal Singh Grewal, Principal, Guru Nanak Engineering College, Ludhiana ;

27. Mr. P. L. Tandon, Director-General, National Council of Applied Economic Research, Indraprastha Estate, New Delhi ;

28. Professor Rasheeduddin Khan, Member Parliament, C-1/13, Pandara Park, New Delhi ;

29. Mr. R. S. Chitkara Retired Director, University Education, Ministry of Education & Social Welfare, B-2/59, Safdarjung Enclave, New Delhi ;

30. Justice R. P. Khosla, Retired Judge, Panjab & Haryana High Court, 305, Sector 10-B, Chandigarh ;

31. Mr. Sudhakar Pandey, Member Parliament, 42 Ashoka Road, New Delhi ;

32. Dr. Shiv Dayal, Mehar Chand Mahajan Professor and Head, Department of Laws, Punjab University, Chandigarh.

33. Dr. S. C. Dube, Director, Indian Institute of Advanced Study, Simla ; and

34. Dr. Kewal Krishna Dhir, Lecturer in Botany, Panjab University, Chandigarh.

[No. 10-VC/DS]

V. PHADKE,
Secy. to the Vice-President,
and Chancellor of the Punjab University.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(राजस्व पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1976

स्टाम्प

का. आ. 4769.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से, जो महाराष्ट्र आवास बोर्ड, बम्बई द्वारा जारी किये जाने वाले एक करोड़ दस लाख रुपये मूल्य के डिबेंचरों पर, उक्त अधिनियम के अधिन प्रभार्य हैं, एसद्द्वारा छूट देती है ।

[सं. 64/76-स्टाम्प/फा. सं. 471/83/76-सी. शु-7]

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING
(Revenue Wing)

ORDER

New Delhi, the 9th December, 1976

STAMPS

S.O. 4769.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby remits the duty with which the debentures to the value of one crore and ten lakhs of rupees, to be issued by the Maharashtra Housing Board, Bombay, are chargeable under the said Act.

[No. 64/76-Stamps/F. No. 471/83/76-CUS. VII]

आदेश

का. आ. 4770.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से, जो, महाराष्ट्र आवास बोर्ड, बम्बई द्वारा 1974-75 में जारी किये गये एक करोड़ दस लाख रुपये मूल्य के डिबेंचरों पर, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, एतद् द्वारा छूट देती है ।

[सं. 63/76-स्टाम्प/फा. सं. 471/83/76-सी. शु-7]

एस. डी. रामास्वामी, अवर सचिव

ORDER

S.O. 4770.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the debentures to the value of one crore and ten lakhs of rupees floated in 1974-75 by the Maharashtra Housing Board, Bombay, are chargeable under the said Act.

[No. 63/76-Stamps/F. No. 471/83/76-Cus. VII]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1976

सीमा-शुल्क

का. आ. 4771.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हैदराबाद और विशाखापतनम एयरपोर्टों को, वायुयानों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित आयातित वायुयान पुर्जों, उपसाधनों और सामग्री को उतारने के लिए सीमाशुल्क एयरपोर्टों के रूप में एतद्द्वारा नियत करती है और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की दिनांक 25 मई, 1974 की अधिसूचना सं. 50/74-सीमाशुल्क, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "कानपुर और लखनऊ" शब्दों के स्थान पर "कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद और विशाखापत्तनम्" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं. 447/76-सी. शु./फा. सं. 481/12/76-सी. शु.-7]

यू. के. सेन., अवर सचिव

New Delhi, the 18th December, 1976

CUSTOMS

S.O. 4771.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Hyderabad and Visakhapatnam airports as Customs airports for the unloading of imported aircraft parts, accessories and materials required for the manufacture of aircrafts and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 50/74-Customs dated the 25th May, 1974, namely :—

In the said notification, for the words "Kanpur and Lucknow", the words "Kanpur, Lucknow, Hyderabad and Visakhapatnam" shall be substituted.

[No. 447/76-Customs/F. No. 481/12/76-Cus. VII]

U. K. SEN, Under Secy.

निर्माण और आवास मन्त्रालय

(दिल्ली विकास प्राधिकरण)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4772.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । इस संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दें वे अपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें ।

संशोधन :

1003.4 वर्ग मीटर (1200 वर्गगज) का क्षेत्र जो दिल्ली मुख्य योजना में 'कृषि उपयोग' के अन्तर्गत नर्सरी उपयोग हेतु निर्धारित है तथा जो उत्तर में जूलोजिकल पार्क, दक्षिण पूर्व में नर्सरी पार्क व पश्चिम में (सुन्दर नगर) आवासीय क्षेत्र से घिरा हुआ है इसको अब "सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाओं (सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान)" के उपयोग हेतु परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है ।

शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है ।

[सं. एफ. 16(31)/76-एम. पी.]

हृदय नाथ फोतेदार, सचिव

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

(Delhi Development Authority)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th December, 1976

S.O. 4772.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

The land use of an area measuring 1003.4 sq. mts. (1200 sq. yds.), earmarked for 'Nurseries use', under the heading of "Agricultural Use" in the Master Plan for Delhi and surrounded by zoological park in the north, nurseries area in the south and east, and residential area (Sunder Nagar) in the west, is proposed to be changed to "Public & Semi-Public Facilities (social & cultural institutions)".

2. The plan, indicating the proposed modification, will be available for inspection at the office of the Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 16(31)/76-M.P.]

H. N. FOTEDAR, Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4773.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8, मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने डोड्डबल्लापुर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-1-1977 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-6/76-पी.एच.बी.]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O. 4773.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-1977 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Dodballapur Telephone Exchange, Karnataka Circle.

[No. 5-6/76-PHB.]

का. आ. 4774.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाकतार महानिदेशक ने केशोद टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-1-1977 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-11/76-पी.एच.बी.]

म. च. वर्मा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.)

S.O. 4774.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-1977 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Keshod Telephone Exchange, Gujarat Circle.

[No. 5-11/76-PHB.]

M. C. VERMA, Assistant Director General (PHB)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4775.—केन्द्रीय सरकार, रेल यात्री सीमाकर अधिनियम 1956 (1956 का 69) की धारा 2 के खण्ड (ग) के अनुसरण में, 1 जनवरी, 1977 से 28 फरवरी, 1977 तक की अवधि के लिए, "झुशी" को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक अधिसूचित स्थान घोषित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त होगी।

[सं० एफ०(X) 1-76/5/1-I)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

New Delhi, the 10th December, 1976

S.O. 4775.—In pursuance of clause (c) of Section 2 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 (69 of 1956), the Central Government hereby declares "JHUSI" to be a notified place for the purposes of the said Act, for the period from the 1st January, 1977 to the 28th February, 1977.

2. This notification shall come into force on the 1st January, 1977.

[No. F(X)I-76/5/1-I.]

का० आ० 4776.—केन्द्रीय सरकार, रेल यात्री सीमाकर अधिनियम, 1956 (1956 का 69) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं० एफ० (X) I-71/टी एक्स-19/1~ VIII, तारीख, 17 जून, 1971 को अधिक्रान्त करते हुए—

(क) इससे उपाबद्ध अनुसूची I के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों को उन दरों के रूप में नियत करती है जिन पर, 1 जनवरी, 1977 से 28 फरवरी, 1977 तक की अवधि के लिए, उक्त अनुसूची I के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचित स्थानों से या तक रेल द्वारा ले जाए जाने वाले सभी यात्रियों पर, प्रत्येक रेल टिकट की बाबत सीमा-कर उद्ग्रहीत किया जाएगा, और

(ख) इससे उपाबद्ध अनुसूची II के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों को उन दरों के रूप में नियत करती है जिन पर, 1 मार्च, 1977 से, उक्त अनुसूची II के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचित स्थानों से या तक रेल द्वारा ले जाए जाने वाले सभी यात्रियों पर, प्रत्येक रेल-टिकट की बाबत सीमा-कर उद्ग्रहीत किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना के प्रथम पैरा का खण्ड (क) 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त होगा और उक्त धारा का खण्ड (ख) 1 मार्च, 1977 को प्रवृत्त होगा।

अनुसूची I

1	2			
अधिसूचित स्थान का नाम	दर्जा	एक ओर के प्रत्येक टिकट पर सीमा कर की दरें		
		वयस्क		3 से 12 वर्ष तक के बच्चे
1. इलाहाबाद जंकशन		थोड़ी दूरी के यात्रियों के लिए (66 कि० मी० से 242 कि०मी० तक)	लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए (242 कि० मी० से आगे)	थोड़ी दूर के यात्रियों के लिए (66 कि० मी० 242 कि० मी० से 242 कि०मी० से आगे) तक)	लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए
2. इलाहाबाद नगर					
3. दारागंज					
4. नैनी जंकशन					
5. प्रयाग					
6. प्रयाग घाट (जब खुला हो)					
7. फफमऊ		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
8. सूबेदारगंज	वातानुकूलित या पहला दर्जा/टू टायर वातानुकूलित शायिका दर्जा	1.40	1.50	0.70	0.75
9. बम्हरौली	वातानुकूलित कुर्सी कार दर्जा	0.90	1.00	0.45	0.50
10. झुशी	दूसरा दर्जा	0.40	0.50	0.20	0.25

अनुसूची II

1		2			
1. इलाहाबाद जंक्शन	वातानुकूलित या पहला	0.50	0.75	0.25	0.40
2. इलाहाबाद नगर	दर्जा/टू टायर वातानु-				
3. दारागंज	कूलित शायिका दर्जा				
4. नैनी जंक्शन	वातानुकूलित कुर्सी	0.50	0.75	0.25	0.40
5. प्रयाग	कार दर्जा				
6. प्रयाग घाट (जब खुला हो)	दूसरा दर्जा	0.10	0.20	0.5	0.10
7. फाफामऊ					
8. सूबेदारगंज					
9. बम्हरौली					

स्पष्टीकरण :—वापसी टिकट पर सीमाकर, इसमें नियत दरों से दोगुना होगा ।

[सं० एफ० (X) I-76/5/1-II]

बी० मोहन्ती, सचिव

S.O. 4776.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 (69 of 1956) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. F (X) I-71/TX-19/1-VII, dated the 17th June, 1971, the Central Government hereby—

(a) fixes the rates specified in column (2) of Schedule I annexed hereto as the rates at which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket on all passengers carried by railway from or to the notified places specified in column (1) of the said Schedule I for the period from the 1st January, 1977 to the 28th February, 1977, and

(b) fixes the rates specified in column (2) of Schedule II annexed hereto as the rates at which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket on all passengers carried by railway from or to the notified places specified in column (1) of the said Schedule II with effect from the 1st March, 1977.

2. Clause (a) of the first paragraph of this notification shall come into force on the 1st January, 1977 and clause (b) of the said paragraph shall come into force on the 1st March, 1977.

SCHEDULE I

(1)		(2)			
Name of notified places	Class of Accommodation	Rates of terminal tax per single railway ticket			
		Adult		Children between 3 & 12 years of age	
		Short distance passengers (66 Kms-242 Kms)	Long distance passengers (over 242 Kms)	Short distance passengers (66 Kms-242 Kms)	Long distance passengers (over 242 Kms)
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1. Allahabad Junction	Air Conditioned or I	1.40	1.50	0.70	0.75
2. Allahabad City	Class/Two tier-A.C.				
3. Daraganj	Sleeper Class.				
4. Naini Junction	A.C. Chair Car Class.	0.90	1.00	0.45	0.50
5. Prayag	II Class.	0.40	0.50	0.20	0.25
6. Prayag Ghat (when opened)					
7. Phaphamau					
8. Subedarganj					
9. Bamhrauli					
10. Jhusi					

SCHEDULE II

1. Allahabad Junction	Air Conditioned or I	0.50	0.75	0.25	0.40
2. Allahabad City	Class/Two tier A.C.				
3. Daraganj	Sleeper Class.				
4. Naini Junction	A.C. Chair Car Class.	0.50	0.75	0.25	0.40
5. Prayag	II Class.	0.10	0.20	0.05	0.10
6. Prayag Ghat (when opened)					
7. Phaphamau					
8. Subedarganj					
9. Bamhrauli					

Explanation : The terminal tax on a return ticket shall be double the rates fixed therein.

[No. F (X)-I-76/5/1-II]

B. MOHANTY, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.